09

अध्याय

उद्योग: स्थायी विकास

उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में मुख्य स्थान रखता है यह औसतन वित्त वर्ष 12 और वित्त वर्ष 21 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद का 31 प्रतिशत था और इसने 12.1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार दिया। वित्त वर्ष 23 में, भारतीय उद्योग को कुछ असाधारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा क्योंकि इस दौरान रूसी-यूक्रेन संघर्ष शुरु हो गया था। इससे कई आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक उछाल आया। खाद्य तेल, कच्चा तेल, उर्वरक और खाद्यान्न की कीमतें तेजी से बढ़ीं। ये कीमतें कई महीनों तक ऊंचे स्तर पर बनी रहीं। आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के एक और दौर का खतरा सामने आया, लेकिन वे उतने गंभीर नहीं थे जितनी कि आशंका थी। फिर भी, आवश्यक वस्तुओं की कीमत और उपलब्धता दोनों में वित्त वर्ष 22 की वसूली को मजबूत करने तथा इसे और तेज करने के उद्योग की उम्मीद में सेंध लगाने की क्षमता थी। यह कहना उचित है कि भारतीय उद्योग ने कठिन परिस्थितियों में स्वंय को काफी हद तक मुक्त कर लिया। वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही के लिए उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर औद्योगिक क्षेत्र द्वारा समग्र सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) 3.7 प्रतिशत बढ़ा, जो पिछले दशक की पहली छमाही में प्राप्त 2.8 प्रतिशत की औसत वृद्धि से अधिक है।

वित्त वर्ष 2022 के बाद से मजबूत घरेलू परिस्थितियों ने औद्योगिक विकास को एक मांग प्रोत्साहन प्रदान किया है। वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही में सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) वित्त वर्ष 2015 के बाद से सभी छमाहियों, पहली छमाही या दूसरी छमाही में सबसे अधिक था। इसके अलावा, वित्त वर्ष 22 का मजबूत निर्यात प्रदर्शन, वित्त वर्ष 203 की पहली छमाही में कुछ हद तक जारी रहा। वर्ष की इस छमाही में, सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात वित्त वर्ष 2016 के बाद से सबसे अधिक रहा है। हालांकि, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में लगातार उच्च मुद्रास्फीति और बढ़ती ब्याज दरों के कारण निर्यात की वर्ष-दर-वर्ष (वाईओवाई) वृद्धि का प्रदर्शन, पहली तिमाही से दूसरी तिमाही तक घटने के कारण पहली छमाही में कम होना शुरू हो गया। निवेश की मांग में वृद्धि औद्योगिक विकास के लिए एक और शक्तिशाली प्रोत्साहन के रूप में सामने आयी है। यह महामारी से पहले के वर्षों की तुलना में वर्तमान और पिछले वर्ष में केंद्र सरकार के संवर्धित कैपेक्स द्वारा सक्रिय किया गया है। इस उछाल ने निजी निवेश में भी भीड़ बढ़ा दी है, जो पहले से ही दबी हुई मांग, निर्यात प्रोत्साहन और कॉर्पोरेट बैलेंस शीट को मजबूत करने पर उत्साहित है।

मांग प्रोत्साहन के लिए उद्योग की आपूर्ति प्रतिक्रिया मजबूत रही है, जैसा कि उच्च-आवृत्ति संकेतकों में देखा गया है। पीएमआई विनिर्माण, जुलाई 2021 से 18 महीनों के लिए विस्तार क्षेत्र में रहा है, और इसके उप-सूचकांक इनफट लागत दबावों में कमी, आपूर्तिकर्ता वितरण समय में सुधार, मजबूत निर्यात ऑर्डर और भविष्य के उत्पादन का संकेत देते हैं। जबकि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के उपभोक्ता टिकाऊ घटक में वृद्धि 'दबी हुई' मांग के जारी होने के कारण है जबकि पूंजीगत वस्तुओं और बुनियादी ढांचे/निर्माण वस्तुओं में वृद्धि एक अच्छे निवेश चक्र की शुरुआत का संकेत है जिसका नेतृत्व निजी क्षेत्र द्वारा किए जाने की उम्मीद है। कोयला, उर्वरक, सीमेंट, बिजली, स्टील और रिफाइनरी उत्पादों के आठ प्रमुख उद्योगों की वृद्धि स्थिर रही है, जो औद्योगिक गतिविधियों में व्यापक गति को

दर्शाता है। हालांकि, विनिर्माण परिदृश्य विभिन्न श्रेणियों में असमान वृद्धि दर्शाता है, जिसमें ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उद्योगों ने प्रभावशाली प्रदर्शन दर्ज किया है जबकि कपड़ा जैसे क्षेत्रों में धीमी वृद्धि दिखाई दे रही है, क्योंकि इन उत्पादों की निर्यात मांग वैश्विक उत्पादन और मांग में कमी के साथ कम हो रही है।

जनवरी 2022 से स्पष्ट वृद्धि के साथ, बैंक ऋण में वृद्धि ने औद्योगिक विकास के साथ गति बनाए रखी है। आपातकालीन क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की शुरुआत से सहायता प्राप्त सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के ऋण में भी आंशिक रूप से उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। जबकि कुल ऋण में वृद्धि, सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योगों द्वारा मांगी गई ऋण में वृद्धि से प्रेरित है, बड़े उद्योगों ने वित्त वर्ष 23 की शुरुआत से अपने ऋण की गति को बढ़ाना शुरू कर दिया है क्योंकि वे अस्थिर ऋण और इक्विटी बाजार से पूंजी जुटाने की अपनी गति को कम करना चाहते हैं। बढ़ती क्षमता उपयोग और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश के साथ संयुक्त रूप से ऋण मांग में मजबूत वृद्धि, भविष्य की मांग के संबंध में व्यवसायों के आशावाद को रेखांकित करती है।

बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के बीच, वित्त वर्ष 23 की पहली छमाही में विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में कमी आई है। हालांकि, अंतर्वाह पूर्व-महामारी के स्तर से काफी ऊपर रहा, जो संरचनात्मक सुधारों और व्यापार करने में आसानी में सुधार के उपायों से प्रेरित था, जिससे भारत दुनिया में सबसे आकर्षक एफडीआई गंतव्यों में से एक बन गया।

इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के महत्व में वृद्धि जारी है क्योंकि इसके अनुप्रयोग व्यापक हो गए हैं। संचार सेवाओं में निरंतर सुधार द्वारा समर्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, उत्पादकता, कुशल सेवा वितरण और सामाजिक परिखर्तन में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा। इस उद्योग के महत्वपूर्ण विकास चालक मोबाइल फोन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। मोबाइल फोन सेगमेंट में, भारत विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है, जिसके हैंडसेट का उत्पादन वित्त वर्ष 15 में 6 करोड़ यूनिट से बढ़कर वित्त वर्ष 21 में 29 करोड़ यूनिट हो गया है।

भारतीय फार्मास्युटिकल्स उद्योग वैश्विक फार्मास्यूटिकल्स उद्योग में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। मात्रा के आधार पर फार्मा उत्पादों के उत्पादन में भारत दुनिया भर में तीसरे और मूल्य के आधार पर 14वें स्थान पर है। यह क्षेत्र विश्व स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है, जो मात्रा के आधार पर वैश्विक आपूर्ति में 20 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है, और 60 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ विश्व स्तर पर अग्रणी वैक्सीन निर्माता भी है। वैश्विक व्यापार व्यवधानों और कोविड-19 से संबंधित उपचारों की मांग में गिरावट के बावजूद सकारात्मक वृद्धि को बनाए रखते हुए फार्मा निर्यात का प्रदर्शन मजबूत रहा है। सितंबर 2022 तक फार्मा क्षेत्र में संचयी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है।

महामारी और रूस-यूक्रेन संघर्ष ने वैश्विक अर्थ व्यवस्था के लिए आपूर्ति श्रृंखला के झटके के जोखिम को प्रदर्शित किया है। जैसा कि कंपनियां लचीलापन बनाने के लिए अपनी विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला रणनीतियों को अपनाती हैं, भारत के पास इस दशक में वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने का एक अनूठा अवसर है। इस संदर्भ में, सरकार की मेक-इन-इंडिया पहल ने घरेलू विनिर्माण क्षमताओं में अंतर को दूर करते हुए निवेश को सुगम बनाया है, नवाचार को बढ़ावा दिया है और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है। 14 श्रेणियों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं ने इसे और पूरक बनाया है, क्योंकि अगले पांच वर्षों में इसके 3 लाख करोड़ रुपये के कैपेक्स को आकर्षित करने की उम्मीद है और 3 मिलियन से अधिक रोजगार पैदा करने की क्षमता है। मध्यम अवधि में, योजना घरेलू विनिर्माण क्षमता का निर्माण करके शुद्ध आयात को कम करने में मदद करेगी जो घरेलू और वैश्विक जरूरतों को पूरा करेगी।

परिचय

9.1 उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख स्थान रखता है यह औसतन वित्त वर्ष 12 और वित्त वर्ष 21 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद का 31 प्रतिशत था और इसने 12.1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार दिया। आर्थिक विकास और रोजगार में योगदान देने वाले अन्य क्षेत्रों के साथ अनेक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंधों के माध्यम से इस क्षेत्र की प्रासंगिकता की पहचान की जा सकती है। सबसे पहले, यह सुनिश्चित करता है कि घरेलू उत्पादन घरेलू मांग को समायोजित कर सकता है और आयात पर निर्भरता कम कर सकता है। जिससे व्यापार और चालू वाता शेष के सुधार में सहायता मिलती है। दूसरा, औद्योगिक विकास के गुणक प्रभाव होते हैं, जो रोजगार वृद्धि में परिवर्तित होते हैं। कपड़ा और विनिर्माण जैसे कुछ उद्योगों में उच्च रोजगार लोच है। तीसरा, औद्योगिक विकास बैंकिंग, बीमा, रसद आदि जैसे सेवा क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देता है।

Table IX.1: औद्योगिक घटकों का विकास एंव भागीदारी (प्रतिशत में)

	प्रतिशत में वृद्धि		वित्त वर्ष 22 के सापेक्ष वित्त वर्ष 23 में वास्तविक जीवीए वृद्धि	वित्त वर्ष 20 के सापेक्ष वित्त वर्ष 23 में वास्तविक जीवीए वृद्धि	वित्त वर्ष 23 के सकल जीवीए में भागीदारी
	छमाही 1:वित्त वर्ष23	छमाही 2:वित्त वर्ष 23 (अनुमानित)			
उद्योग	3.7	4.5	4.1	11.1	30.0
वनन और उत्वनन	2.2	2.6	2.4	4.4	2.3
उत्पादन	0.1	3.0	1.6	11.0	17.3
बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएं	10.0	7.9	9.0	13.0	2.3
विनिर्माण	11.5	7.3	9.1	12.8	8.1
कुल जीवीए	**9.0**	**4.7**	**6.7**	**9.8**	-

स्रोत: एनएसओ, , सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
नोट: वित्त वर्ष 23 के लिए ऑकड़े, पहला अग्रिम अनुमान प्रदर्शित करते है

2. औद्योगिक उत्पादन देश में औद्योगिक आय बढ़ाने का एक साधन है। औद्योगिक जीवीए की माप के अनुसार, औद्योगिक आय में वृद्धि ने वित्त वर्ष 20 के पूर्व-महामारी वर्ष के बाद से अर्थव्यवस्था में समग्र जीवीए वृद्धि के साथ गतिक्रम को बनाए रखा है। उत्पादन जीवीए, जो औद्योगिक जीवीए में 50 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है, समग्र जीवीए की तुलना में और भी अधिक दर से बढ़ा है। उद्योग क्षेत्र में वित्त वर्ष 22 में 10.3 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि की तुलना में वित्त वर्ष 23 में 4.1 प्रतिशत की मामूली वृद्धि देखी गई। इसके इनपुट लागत-पुश दबावों, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों और चीन के लॉकडाउन के कारण आवश्यक इनपुट की उपलब्धता को प्रभावित करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था को धीमा करने की संभावना है। आधारभूत प्रभाव के लुप्त होने का असर वित्त वर्ष 23 में विकास पर भी पड़ा होगा। एक सकारात्मक स्थिति पर, दूसरी छमाही: वित्त वर्ष 23 का अनुमान, दोनों वार्षिक और क्रमिक रूप से समग्र औद्योगिक विकास, विशेष रूप से उत्पादन क्षेत्र में सुधार प्रदर्शित करता है। यदि अन्य चीजें पूर्ववत रहें तो, इनपुट कीमतों में कमी और अनुकूल मांग स्थितियों से विकास को समर्थन मिलेगा।

3. इस अध्याय में सर्वेक्षण चालू वित्त वर्ष में भारतीय उद्योग के प्रदर्शन की समीक्षा करेगा। यह औद्योगिक विकास के लिए मांग उत्तेजक, उद्योग की आपूर्ति प्रतिक्रिया, उद्योग के लिए ऋण रुझान और भारत के औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी निवेश की जांच करता है। अध्याय प्रमुख सह-उद्योगों के विकास और उनकी चुनौतियों का भी समाधान करता है। अंतत:, यह वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की भारत की आकांक्षाओं और संभावनाओं का मूल्यांकन करता है।

औद्योगिक विकास के लिए मांग प्रोत्साहन

4. वित्त वर्ष 23, एक माह पुराने रूसी-यूक्रेन संघर्ष के साथ शुरू हुआ जिसमें राहत के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। जैसे-जैसे साल आगे बढ रहा है, जैसे-जैसे संघर्ष स्थिर होता दिख रहा है, हालांकि वैश्विक उत्पादों की कीमतें अभी भी अपने पूर्व-महामारी के स्तर तक कम नहीं हुई हैं। इस प्रकार पूरे वर्ष भर देश में उद्योग को आयातित उच्च इनपुट लागतों का सामना करना पड़ा है। मांग प्रभाव के डर से, उद्योग धीरे-धीरे उच्च उत्पादन लागत की ओर आगे बढ़ा रहा है, जिसके कारण स्थिर लेकिन गैर-वर्धित कोर खुदरा मुद्रास्फीति हो गई है। दूसरी ओर गैर-प्रमुख खुदरा मुद्रास्फीति, जिसमें खाद्य और ऊर्जा घटक शामिल हैं, में गिरावट आ रही है क्योंकि स्थानीय मौसम की चरम सीमाएं कम हो गई हैं और मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए हस्तक्षेप प्रभावी साबित हुए हैं। समग्र खुदरा मुद्रास्फीति में परिणामी कमी ने इस प्रकार महामारी के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता मांग को बनाए रखा है, जिससे वैश्विक विपरीत परिस्थितियों के बावजूद औद्योगिक सुधार हुआ है। वैश्विक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें अब भी कम हो रही हैं और यह भारत की थोक मुद्रास्फीति की घटती दरों में दिवाई दे रही हैं जिससे मुख्य खुदरा मुद्रास्फीति में कमी आने की उम्मीद है जिससे देश में औद्योगिक विकास को और बढ़ावा देने के लिए घरेलू खपत की मांग और अधिक मजबूत हो जाएगी। वित्त वर्ष 23 की पहली छमाही में जीडीपी के हिस्से के रूप में पीएफसीई वित्त वर्ष 15 के बाद सबसे अधिक थी।

5. मजबूत बाहरी मांग ने वित्त वर्ष 22 में भी भारतीय उद्योग की अच्छी तरह से सेवा की, जब वैश्विक वृद्धि में फनः सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए उत्पाद निर्यात अपनी सीमा को पार कर गया था। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अड़चनें कम होने के कारण व्यापार भी संवर्धित हो गया था और बढ़ गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निर्यात प्रोत्साहन वित्त वर्ष 23 की पहली छमाही में यथावत बना रहा। वर्ष की इस छमाही में, सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात वित्त वर्ष 2016 के बाद से सबसे अधिक रहा है। हालाँकि, पहली छमाही में ही निर्यात की गति कम हो रही है क्योंकि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में लगातार उच्च मुद्रास्फीति और बढ़ती ब्याज दरों के कारण निर्यात की साल-दर-साल वृद्धि पहली तिमाही से दूसरी तिमाही तक घट गई है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में निर्यात वृद्धि और धीमी हो सकती है और अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ जाती है तो इसके बाद भी कमजोर रह सकती है। यह भारतीय उद्योग पर निर्भर होगा कि वह अपनी विकास गति को बदले और उस घरेलू बाजार के लिए उत्पादन करे जो वह देश विदेशों से आयात करता है।

6. घरेलू खपत, निर्यात और आयात प्रतिस्थापन के अलावा, निवेश की मांग में वृद्धि, औद्योगिक विकास के लिए एक और शक्तिशाली प्रोत्साहन के रूप में उभरी है। यह महामारी के पूर्व के वर्षों की तुलना में वर्तमान और पिछले वर्ष में केंद्र सरकार के कैपेक्स में उछाल से शुरू हुआ है। इस उछाल में भीड़-भाड़ वाला निजी निवेश भी है, जो पहले से ही दबी हुई खपत की मांग, निर्यात प्रोत्साहन और कॉर्पोरेट तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) को मजबूत करने पर उत्साहित है। वित्त वर्ष 23 की पहली तिमाही में मौजूद 74.3 प्रतिशत क्षमता उपयोग पहले ही वित्त वर्ष 22 की चौथी तिमाही में 75.3 प्रतिशत के चरम बिंदु पर पहुंच गया है, जिस पर नई क्षमताओं के निर्माण में निवेश किया जाता है। वित्त वर्ष 23 के अप्रैल-दिसंबर के दौरान उत्पादन क्षेत्र में घोषित नया निवेश, वित्त वर्ष 20 में इसी स्तर का पांच गुना था। पिछले कई वर्षों में सरकार द्वारा की गई नीतिगत कार्रवाइयों के लिए निवेश में वृद्धि भी जिम्मेदार है। वित्त वर्ष 23 की पहली छमाही में एक शुरुआत की गई है, जिसने वित्त वर्ष 2015 के बाद से सभी छमाहियों में सकल घरेलू उत्पाद में सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) का उच्चतम हिस्सा दर्ज किया है।

चित्र IX.1: उत्पादन क्षेत्र में बढ़ता निजी निवेश

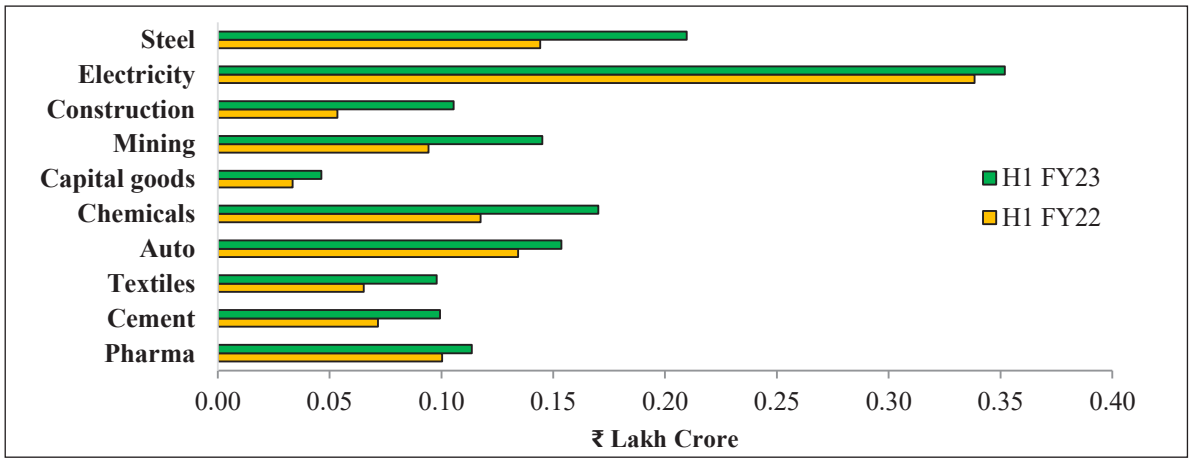

स्रोत: कैपेक्स डेटाबेस, सीएमआईई

बॉक्स IX.1: निजी पूंजी निवेश चक्र का विकास

एक दृष्टिकोण तेजी से उभर रहा है कि निजी क्षेत्र नई सहस्राब्दी के तीसरे दशक में निवेश बढ़ाने के लिए तैयार है। इसकी जड़ें नई सहस्राब्दी के पहले दशक में स्थित हैं जब एक क्रेडिट बूम ने निवेश दरों के बढ़ते स्तरों को वित्तपोषित किया। परिणामस्वरूप, जब तक दूसरा दशक शुरू हुआ, कॉरपोरेट और बैंकों दोनों की बैलेंस शीट दबावग्रस्त हो गई। परिणामस्वरूप, कॉरपोरेट्स ने निवेश से ध्यान हटाकर कर्ज चुकाने पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि बैंकों ने उच्च गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) को देखते हुए ऋण संवितरण को धीमा कर दिया। इसके परिणामस्वरूप, निवेश दर कम हो गई तथा अर्थव्यवस्था धीमी होनी शुरू हो गई। दूसरे दशक के मध्य में, समस्याओं की पहचान की गई और शमन उपाय शुरू किए गए। बैंकों के लिए, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) को उनकी दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान करने के लिए स्थापित किया गया था, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के इक्विटी आधार को मजबूत किया गया था। कॉरपोरेट्स के लिए, GST रोलआउट ने उनके व्यवसाय करने में सुलभता में सुधार किया, जबकि निवेश के वित्तपोषण के लिए उनके लाभ/निवेश योग्य भंडार को बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की दर को घटा दिया गया था। महामारी के दौरान, ईसीएलजीएस के कार्यान्वयन ने एमएसएमई को अतिरिक्त सहायता प्रदान की। परिपक्व होती डिजिटल अवसंरचना और आसान और सस्ते डेटा एक्सेस ने निवेश के माहौल को और समृद्ध किया है।

चित्र A: निजी गैर-वित्तीय क्षेत्र द्वारा उत्तोलन

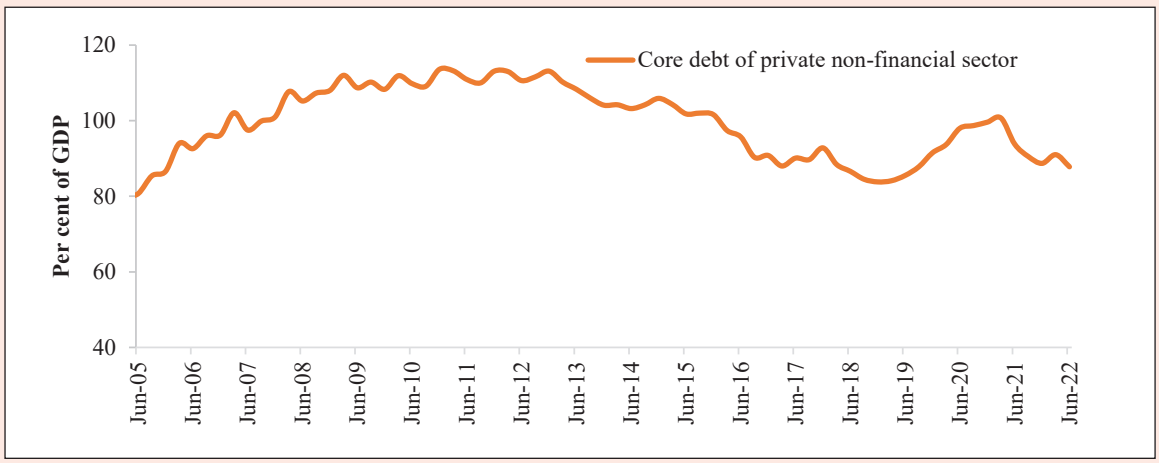

स्रोत: बीआईएस

नोट: गैर-वित्तीय क्षेत्र के लिए ऋण निजी गैर-वित्तीय क्षेत्र की उधारी गतिविधि को आकर्षित करता है।

ऋण में कमी ने कॉर्पोरेट बैलेंस शीट को मजबूत किया है, जैसा कि निजी गैर-वित्तीय क्षेत्र के कम होते मूल ऋण से स्पष्ट है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में निजी गैर-वित्तीय क्षेत्र के लिए ऋण दिसंबर 2010 में 113.0 प्रतिशत के शिखर से दिसंबर 2018 में 83.8 प्रतिशत के निचले स्तर पर आ गया था। इससे पता चलता है कि ऋण में कमी अंत तक पूरा हो गई थी। मई 2019 में चुनावों और सितंबर 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की घोषणा के साथ, यह निवेश और आर्थिक विकास चक्रों में सुधार के रूप में परिणत हुआ होता लेकिन महामारी के कारण हुए व्यवधान के कारण इसमें दो वर्ष का विलम्ब हुआ। बेहतर कॉर्पोरेट प्रदर्शन और जीडीपी में सुधार के कारण निजी गैर-वित्तीय क्षेत्र के मुख्य ऋण के रूप में वित्त वर्ष 2022 की शुरुआत से ऋण में कमी फिर से प्रारंभ हुई जो मार्च 2021 की तिमाही में 100.7 प्रतिशत थी वह जून 2022 की तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद का 87.8 के स्तर तक घट गई।

वित्त वर्ष 23 की पहली छमाही के दौरान, ब्याज कवरेज अनुपात 5 था, जो इसके पांच वर्ष (वित्त वर्ष 20) के औसत 3 से अधिक था। ऋण-इक्विटी अनुपात भी 0.8 से घटकर 0.4 हो गया। इन सुधारों ने वैश्विक पण्य कीमतों में उतार-चढ़ाव और आपूर्ति श्रंखला व्यवधानों से प्रेरित कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं में वृद्धि को और अधिक अवशोषित कर लिया है। दूसरी ओर, वित्त वर्ष 2011 की दूसरी छमाही में लाभ अंतर चरम पर था क्योंकि कम मुद्रास्फीति ने इनपुट लागत को बढ़ने से रोक दिया, जबकि सीमित गतिशीलता ने उपरिव्यय को कम कर दिया। इसके बाद, लाभ अंतर में गिरावट शुरू हो गई क्योंकि बढ़ती वैश्विक पण्य कीमतों के कारण इनपुट लागत में वृद्धि हुई। वैश्विक पण्य कीमतों में गिरावट के साथ, इनपुट लागत में गिरावट आना तय है, और लाभ अंतर के बढ़ने की उम्मीद है। मुनाफे में अपेक्षित वृद्धि और मजबूत बैलेंस शीट ने कॉर्पोरेट क्षेत्र को वित्तीय रूप से मजबूत और शुद्ध बिक्री बढ़ाने के विषय में आशावादी बना दिया है। जुलाई-सितंबर 2022 के दौरान आयोजित आरबीआई का औद्योगिक आउटलुक सर्वेक्षण, वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही तक समाहित समयावधि के लिए उत्पादन, ऑर्डर बुक, रोजगार और लाभ अंतर के लिए आशावाद की ओर इशारा करता है।

चित्र B: निवल बिक्री के बढ़ने की उम्मीद है

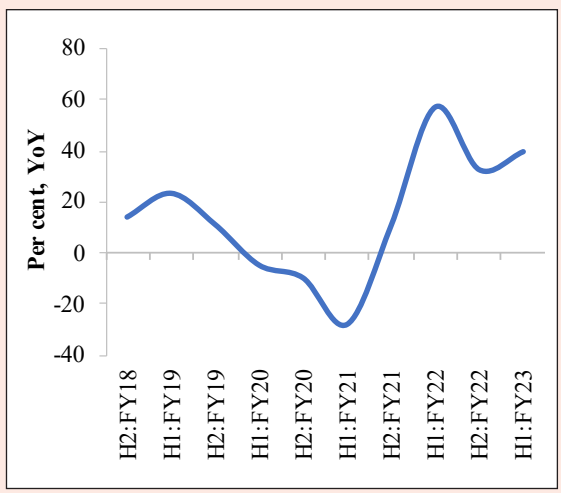

चित्र C: लाभ अंतर में सुधार हो रहा है

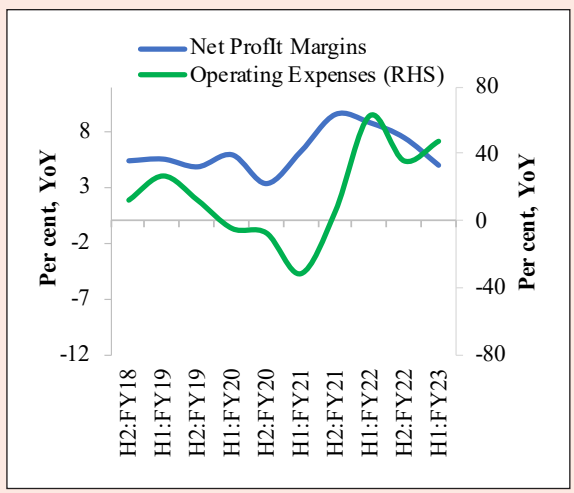

चित्र D: आंशिक रूप से मजबूत नकदी और लाभ

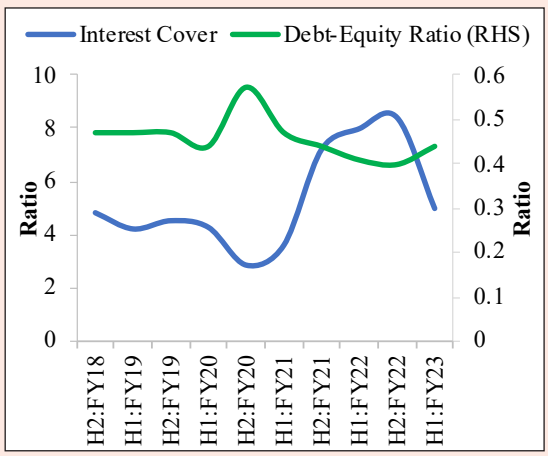

स्रोत: सीएमआईई

चित्र E: क्षमता उपयोग तथा व्यवसाय की आशा

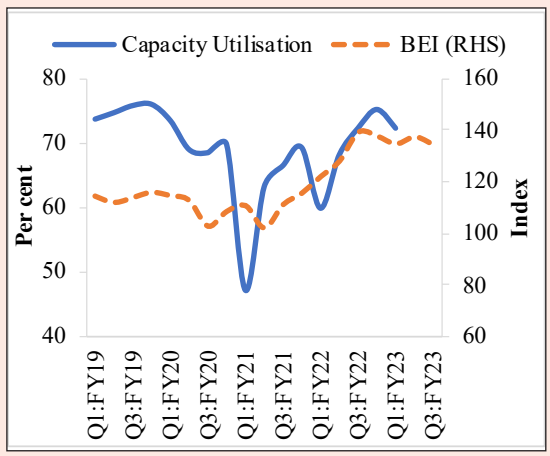

स्रोत: आरबीआई

नोट: बीईआई से तात्पर्य व्यवसाय अपेक्षा सूचकांक है

पहले दशक में क्रेडिट बूम ने गैर-वित्तीय क्षेत्र में बैंकिंग क्षेत्र की अग्रिमों को 2004 में सकल घरेलू उत्पाद के 36.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 2014 में 57.3 प्रतिशत (बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स) कर दिया। जिसके कारण आरबीआई ने एनपीए का अधिक कड़ा मूल्यांकन लागू किया। परिणामत:, एनपीए वित्त वर्ष 2015 में सकल बैंक अग्रिमों के 4.3 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 18 में 11.2 प्रतिशत हो गया। तथापि, आईबीसी कोड के प्रवर्तन और ऋण संवितरण के लिए अधिक अनुशासित दृष्टिकोण के साथ, एनपीए वित्त वर्ष 21 में 7.3 प्रतिशत और सितंबर 2022 में सात वर्ष के निचले स्तर 5.0 प्रतिशत पर आ गया। पूंजी-से-जोखिम-भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) और प्रावधान कार्यक्षेत्र अनुपात (पीसीआर) में भी सुधार हुआ है और ये सितंबर 2022 में क्रमश: 16.0 प्रतिशत और 71.5 प्रतिशत पर रहे। उचित रूप से पूंजीकृत बैंक, उधार देने के लिए तैयार और इच्छुक हैं और कॉरपोरेट्स वित्तीय रूप से मजबूत और उधार लेने के इच्छुक हैं, ऋण-निवेश चक्र तीसरे दशक में तेजी के लिए तैयार है।

उद्योग की आपूर्ति प्रतिक्रिया

7. मांग प्रोत्साहन के लिए उद्योग की आपूर्ति प्रतिक्रिया मजबूत रही है, जैसा कि उच्च-आवृत्ति संकेतकों में देखा गया है। उदाहरण के लिए, पीएमआई-उत्पादन, जुलाई 2021 से 18 महीनों के लिए विस्तारक क्षेत्र में बना हुआ है। दिसंबर 2022 में, पीएमआई-उत्पादन के उप-सूचकांकों ने, इनपुट लागत दबावों की आसान गति, आपूर्तिकर्ता वितरण समय में सुधार, मजबूत निर्यात आदेश और भविष्य के आउटपुट का संकेत दिया। इनपुट लागत मुद्रास्फीति में नरमी से भी उत्पादन कीमतों की गति में कमी आई है। हालाँकि, नए निर्यात आदेशों में विस्तार की गति में कमी आई, जो कि वैश्विक मांग में कमी को दर्शाता है।

8. उत्पादन आउटपुट की निरंतर वृद्धि समग्र आईआईपी उत्पादक टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं में ''दबी हुई'' खपत मांग के साथ देखी जा सकती है। पूंजीगत वस्तुओं और बुनियादी ढांचे/विनिर्माण वस्तुओं के उत्पादन में मजबूत वृद्धि अगले वित्तीय वर्ष में निजी क्षेत्र में निवेश चक्र की शुरुआत का संकेत है।

चित्र IX.2: पीएमआई उत्पादन विस्तारक क्षेत्र में बना हुआ है

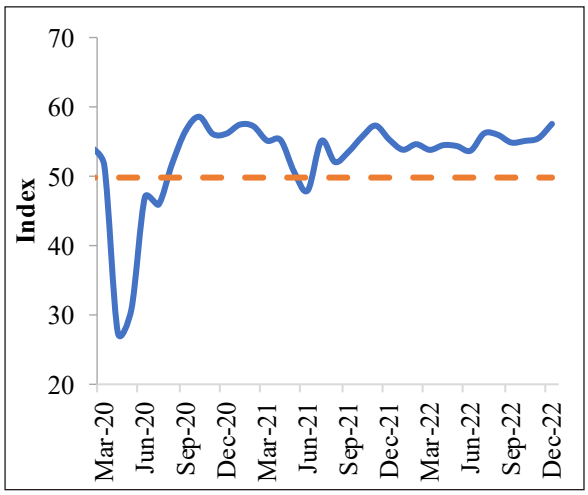

स्रोत: आईएचएस मार्किट

चित्र IX.3: आईआईपी के उप-सूचकांक मजबूत गति से बढ़ रहे हैं (अप्रैल-अक्टूबर)

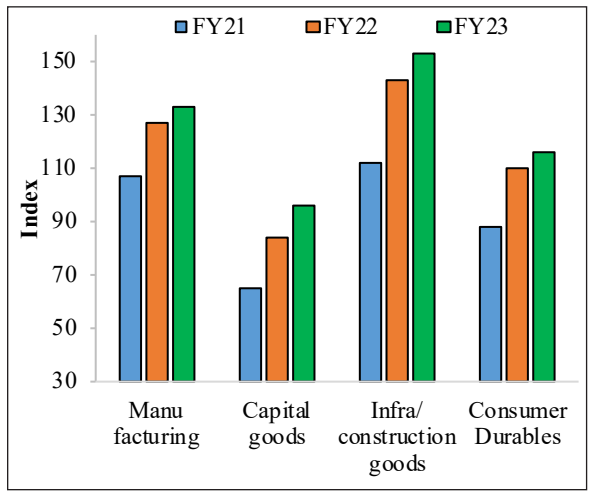

स्रोत: एमओएसपीआई

9. कोयला, उर्वरक, सीमेंट, स्टील, बिजली, रिफाइनरी उत्पाद, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के आठ प्रमुख उद्योग, उद्योगों में उत्पादन की मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण हैं। औद्योगिक गतिविधियों में व्यापक गति को दर्शाते हुए, इन उद्योगों में वृद्धि स्थिर रही है। उनकी वृद्धि इस महत्व को रेखांकित करती है कि राष्ट्र वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ने वाली महामारी और रूस-यूक्रेन संघर्ष के बाद मूल क्षमताओं की स्वदेशी उपस्थिति से जुड़ रहे हैं।

चित्र IX.4: प्रमुख उद्योगों के सूचकांक के घटकों में स्थिर वृद्धि

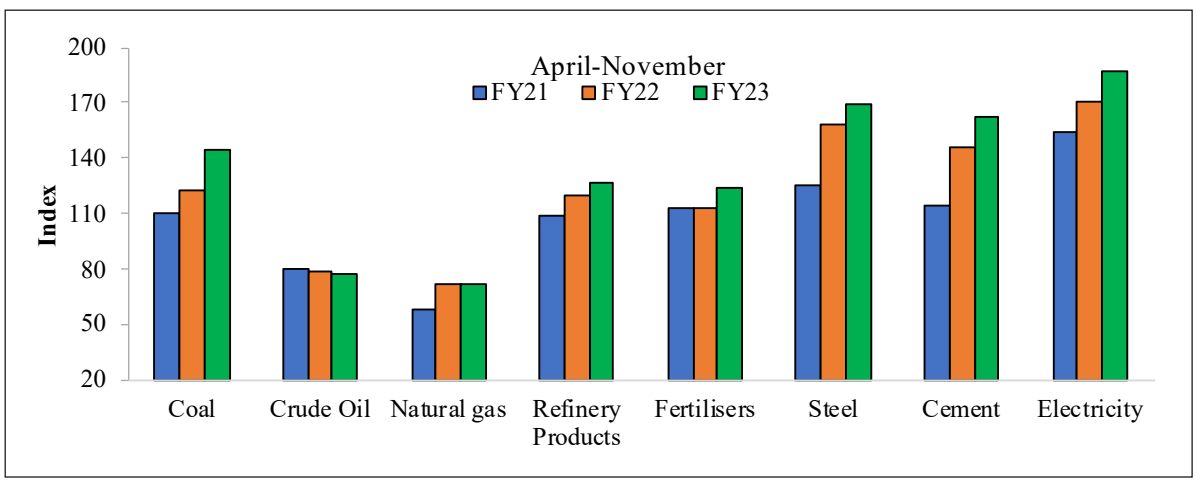

स्रोत: डीपीआईआईटी

10. औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि अधिक होती, लेकिन वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ा। मौसमीपन, खनन और उत्खनन और विनिर्माण के संबंध में उत्पादन की वृद्धि को बाधित करने में भागीदार रहा, क्योंकि वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में कुल वर्षा वित्त वर्ष 22 की दूसरी तिमाही की तुलना में लगभग 12 प्रतिशत अधिक थी। इसके अलावा, उच्च वर्षा के कारण तापमान ठंडा हो गया, बिजली की मांग घट गई और इसलिए उत्पादन वित्त वर्ष 22 की दूसरी तिमाही की तुलना में वित्त वर्ष 23 की दूसरी तिमाही में 5 प्रतिशत से भी कम बढ़ा।

चित्र IX.5: उच्च वर्षा द्वारा सीमित जीवीए निर्माण (विनिर्माण उत्पादन के लिए एक प्रॉक्सी)

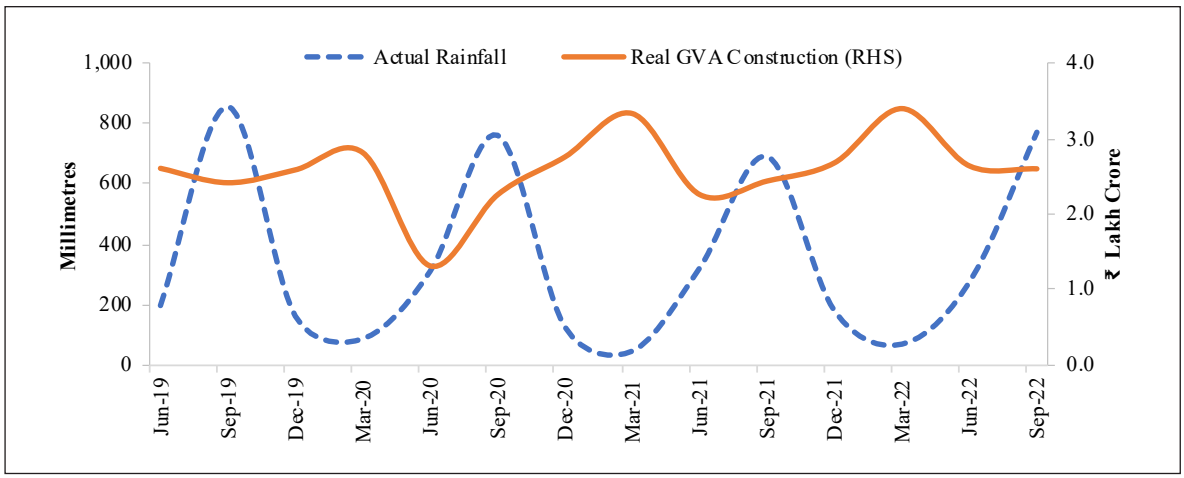

स्रोत: एमओएसपीआई

11. ऐसा प्रतीत होता है कि विनिर्माण उत्पादन, माल सूची में बड़े बिल्ड-अप से बाधित हुआ है। वित्त वर्ष 23 की दूसरी तिमाही में समाप्त होने वाली लगातार पांच तिमाहियों के लिए, भंडार में वार्षिक जीडीपी की 1.3 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई थी। विनिर्माण जीवीए (विनिर्माण उत्पादन के लिए एक प्रॉक्सी) के विकास के साथ-साथ भंडारों में बदलाख का एक विशिष्ट चक्र की तुलना बताती है कि भंडार में वृद्धि, मौजूदा मांग को पूरा करने वाले संचित भंडार के साथ अपनी गति को धीमा करने की अनुमति देती है। जब भंडार कम होने लगता है तो मौजूदा मांग को पूरा करने के लिए विनिर्माण उत्पादन बढ़ता है और अगले चक्र की शुरुआत से पहले भंडार को भर देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि भंडार बिल्ड-अप ने दूसरी तिमाही में विनिर्माण उत्पादन की वृद्धि को बाधित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

चित्र IX.6: भंडार में बिल्ड-अप और बढ़ी हुई वैश्विक अनिश्चितता के साथ जीवीए विनिर्माण धीमा है

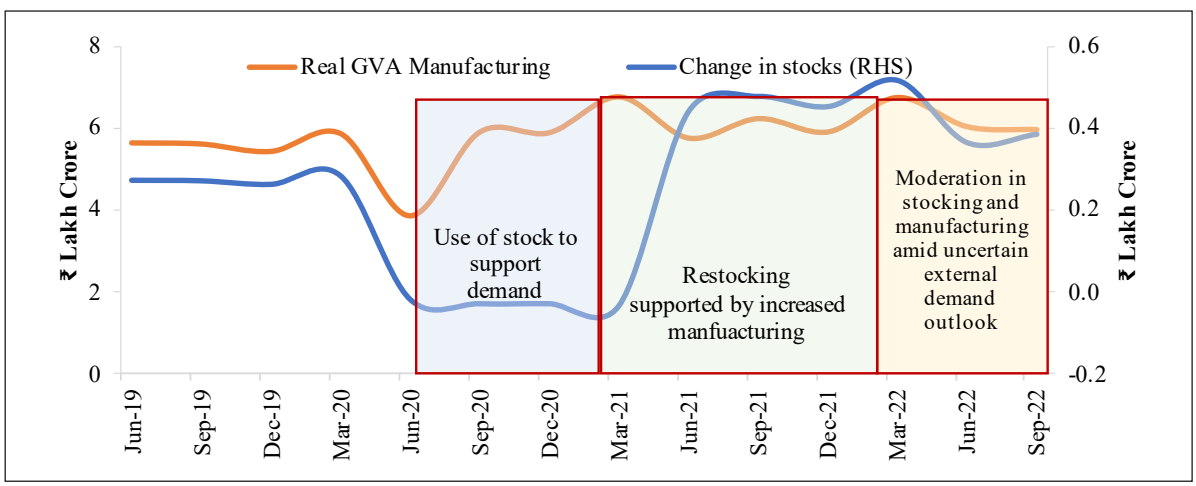

स्रोत: एमओएसपीआई; नोट: भंडारों में परिवर्तन से तात्पर्य जीएफसीएफ में बदलाख से है।

12. विनिर्माण परिदृश्य आगे विभिन्न श्रेणियों में असमान वृद्धि दर्शाता है। उदाहरण के लिए, मजबूत मांग और चिप की कमी को कम करते हुए मोटर वाहन निर्माण खंड के प्रदर्शन में सुधार जारी है। एक आगामी उद्योग, 'कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों' का निर्माण, भी बढ़ रहा है। भारत को सेमीकंडक्टर्स का निर्माण केंद्र बनाने की इच्छुक कई कंपनियों ने इस क्षेत्र में निवेश के दृष्टिकोण को सकारात्मक बना दिया है। कोक

और रिफाइंड पेट्रोलियम का उत्पादन भी बढ़ा है, जिससे वैश्विक बाजार में, जहां कच्चे तेल की कीमतें वित्त वर्ष 22 की तुलना में अधिक थीं वहाँ पर अधिक प्रतिलाभ मिल रहा है। कास्टिक सोडा, सोडा ऐश, उर्वरक और पेट्रोलियम उत्पादों जैसे रसायन और रासायनिक उत्पादों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, जिससे निर्यात में वृद्धि के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में विकास की गति को बनाए रखने में योगदान मिला है। साथ ही, कपड़ा, परिधान और चमड़े सहित कुछ उत्पाद श्रेणियों में धीमी वृद्धि दिवाई दे रही है, क्योंकि वैश्विक उत्पादन और मांग में कमी के साथ इन उत्पादों की निर्यात मांग कम हो रही है। प्रतिकूल आधार प्रभाव और महामारी के प्रभाव के कम होने के कारण फार्मास्युटिकल उत्पादन में वृद्धि धीमी हो गई है।

Table IX.2: विनिर्माण क्षेत्रों में वृद्धि (प्रतिशत, वर्ष-दर-वर्ष)

<0	>0 but <5	>5

	भार	अप्रैल-22	मई-22	जून-22	जुलाई-22	अगस्त-22	सितंबर-22	अक्टूबर-22	नवंबर-22
खाद्य उत्पाद	5.3	3.8	10.1	5.1	-2.6	0.7	4.0	-3.7	9.9
पेय पदार्थ	1	29.2	130.3	45.7	13.1	6.4	12.3	2.7	8.2
तम्बाकू उत्पाद	0.8	22	21.4	52.7	-9.1	-12.8	-0.7	-14.3	-5.0
कपड़ा	3.3	-0.4	5.9	-3.1	-9.0	-12.5	-13.9	-18.7	-9.0
परिधान	1.3	55.2	69.9	42.6	15.1	-18.3	-21.6	-36.6	-11.7
चमड़ा एवं संबंधित उत्पाद	0.5	5	47.5	1.9	-13.5	-16.0	-17.5	-25.5	-2.0
लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद, कार्क	0.2	4.1	54.1	14.4	7.9	-7.9	-3.7	-14.8	-0.5
कागज और कागज के उत्पाद	0.9	-1.9	9.7	8.3	-0.2	-0.1	6.2	-8.2	-2.3
रिकार्डेड मीडिया का मुद्रण और पुनरुत्पादन	0.7	30.1	43	45.1	41.2	27.6	29.1	13.5	22.1
कोक एवं परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद	11.8	10.6	18.1	17.4	7.2	6.6	9.7	-1.0	-9.8
रसायन और रसायन उत्पाद	7.9	4.4	24.3	14.8	7.2	5.7	6.4	-2.5	6.2
फार्मास्यूटिकल्स और औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद	5	-5.5	-13.4	-4.6	-4.7	-17.6	-15.1	-21.2	10.0
रबड़ एवं प्लास्टिक उत्पाद	2.4	-1.5	8.7	5.7	-2.2	-4.4	-2.8	-2.1	5.6
अन्य गैर-धातु खनिज उत्पाद	4.1	6.9	22.1	19.6	0.0	1.4	9.7	-3.7	19.8
मूल धातु	12.8	6.9	16.5	7.2	6.7	4.0	5.7	4.4	8.1
निर्मित धातु उत्पाद,	2.7	-0.4	29.2	14.3	-4.1	-14.4	14.6	-11.8	8.2
कम्प्यूटर, इलैक्ट्रानिक और ऑप्टिकल उत्पाद	1.6	6.3	28.7	43.8	2.8	3.3	-0.2	-11.8	3.0
विद्युत उपकरण	3	8.3	59.6	11	-16.1	-28.5	-31.0	-33.0	1.2
मशीनरी और उपकरण एन.ई.सी.	4.8	5.4	38.8	19.9	4.1	2.9	6.4	-7.2	20.8

	भार	अप्रैल-22	मई-22	जून-22	जुलाई-22	अगस्त-22	सितंबर-22	अक्टूबर-22	नवंबर-22
मोटर वाहन, ट्रेलर और अर्ध-ट्रेलर	4.9	6.5	87.3	31.2	17.8	22.7	29.1	12.2	22.2
अन्य परिवहन उपकरण	1.8	-1.5	126.6	36.2	-1.2	7.8	14.8	-8.1	24.0
फर्नीचर	0.1	59.3	73.7	31.8	32.4	44.1	30.3	6.4	15.7
अन्य निर्माण	0.9	-3.2	18.5	26.4	6.9	4.2	4.8	-31.1	13.1

स्रोत: एमओएसपीआई

उद्योग के लिए बैंक ऋण में मजबूत वृद्धि

13. जनवरी 2022 से क्रमिक उछाल के साथ, बैंक ऋण में वृद्धि ने औद्योगिक विकास के साथ गति बनाए रखी है। एक ओर बैंक ऋण का एक बड़ा हिस्सा बड़े उद्योगों को सौंपा जा रहा है तो दूसरी तरफ ईसीएलजीएस की शुरूआत हो जाने से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को भी क्रेडिट में भी सहायता मिली है। राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसीएल), जो ईसीएलजीएस का संचालन करने वाली एजेन्सी है, के अनुसार लगभग 1.2 करोड़ व्यवसाय इस योजना द्वारा समर्थित हैं, जिनमें से 95 प्रतिशत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम हैं। परिणामत:, उद्योग के सकल ऋण में एमएसएमई[1] की हिस्सेदारी जनवरी 2020 के 17.7 प्रतिशत से बढ़कर नवंबर 2022 में 23.7 प्रतिशत हो गई है। हालांकि कुल ऋण में वृद्धि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों द्व ारा मांगे गए ऋण में वृद्धि से प्रेरित है तथापि, बड़े उद्योगों ने भी वित्त वर्ष 23 की शुरुआत से ऋण प्राप्त करने की गति को बढ़ाना शुरू कर दिया है। कॉरपोरेट बॉन्ड आय और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (एमसीएलआर) के कम होने और कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट में अधिक उतार-चढ़ाव रहने से ऐसा लगता है कि कॉरपोरेट, बॉन्ड मार्केट से फंडिंग के अपने स्रोतों को बैंक कैपिटल में शिफ्ट कर रहे हैं, जहां दरें स्थिर और पूर्वानुमेय बनी हुई हैं। बढ़ते क्षमता उपयोग और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश के साथ ऋण मांग में मजबूत वृद्धि भविष्य की मांग के संबंध में व्यवसायों के आशावाद को रेखांकित करती है।

चित्र IX.7: एमएसएमई द्वारा संचालित उद्योग में दो अंकों की ऋण वृद्धि

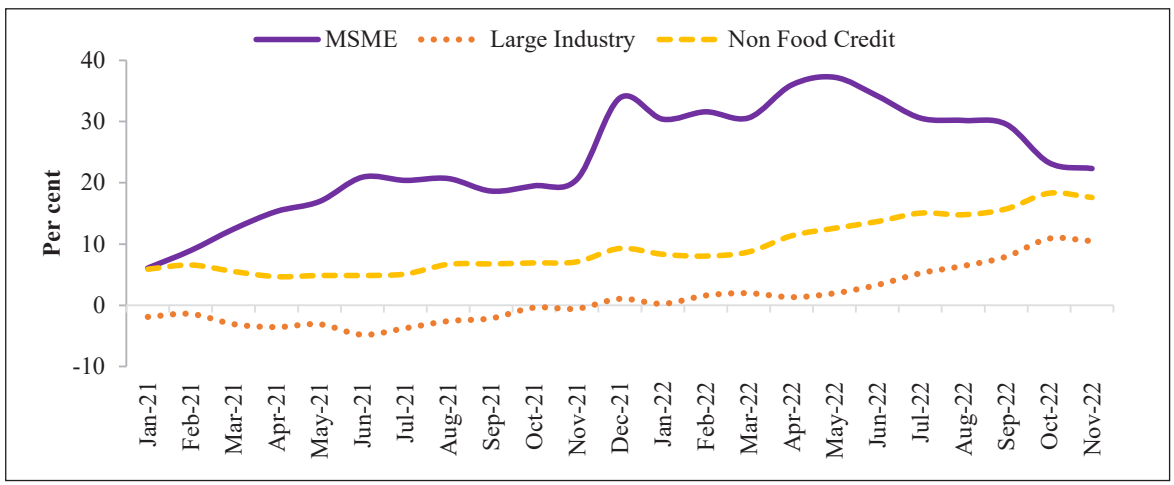

स्रोत: आरबीआई

1 As per the National Credit Guarantee Trustee Company Ltd. (NCGTCL), the agency which operates the ECLGS

Table IX.3: उद्योग उपखंडों में नियोजित ऋण में वृद्धि (प्रतिशत, वर्ष-दर-वर्ष)

-23 0 65

उद्योग	नवंबर-21	अप्रैल-22	नवंबर-22
खनन एवं उत्खनन (कोयले सहित)	13.8	10.9	6.3
खाद्य प्रसंस्करण	6.1	10.7	7.4
पेय और तंबाकू	2.0	4.1	24.4
कपड़ा	8.6	7.1	3.0
चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद	-1.7	7.3	5.9
लकड़ी तथा लकड़ी के उत्पाद	6.6	8.4	15.9
कागज तथा कागज उत्पाद	8.4	9.3	6.6
पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद एवं परमाणु ईंधन	24.6	25.4	65.0
रसायन और रासायनिक उत्पाद	6.4	10.4	19.1
रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	23.3	26.4	18.4
कांच और कांच के बने पदार्थ	-13.2	-3.8	11.0
सीमेंट और सीमेंट उत्पाद	-23.4	-12.2	10.2
मूल धातु और धातु उत्पाद	-15.5	-4.4	15.3
इंजीनियरिंग	5.2	9.7	11.1
वाहन, वाहन के पुर्जे और परिखहन उपकरण	-2.0	6.8	8.3
रत्न और आभूषण	5.0	11.9	-1.2
निर्माण	-8.2	-6.5	2.1
आधारभूत संरचना	6.1	9.7	10.5
अन्य उद्योग	10.9	12.8	25.3

स्रोत: सर्वेक्षण गणना, भारतीय रिजर्व बैंक

14. कपड़ा उद्योग को छोड़कर विनिर्माण क्षेत्र के सभी खण्डों में नवंबर 2022 में ऋण के कुल ऋण में वृद्धि देखी गई। एक ओर ''पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और परमाणु ईंधन'', ''रबर, प्लास्टिक और उनके उत्पाद'', और ''इंजीनियरिंग'' जैसे क्षेत्रों में ऋण की मांग लगातार बनी रही है तो दूसरी ओर पिछले वर्ष में सीमेंट और निर्माण क्षेत्रों में ऋण की वृद्धि में हुआ सुधार निर्माण क्षेत्र के बेहतर दृष्टिकोण को दर्शाता है।

विनिर्माण क्षेत्र में लचीला एफडीआई अंतर्वाह

15. विनिर्माण क्षेत्रों में एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह वित्त वर्ष 21 के 12.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 22 में 21.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। हालाँकि, रूस-यूक्रेन संघर्ष के बाद, वित्त वर्ष 23 की पहली छमाही में विनिर्माण में एफडीआई इक्विटी प्रवाह 6.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा जो वित्त वर्ष 22 की पहली छमाही में प्राप्त 10.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम था। ''कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर'',

''निर्माण गतिविधियां'', ''ऑटोमोबाइल उद्योग'', ''परामर्शी सेवाएं'', ''दवाएं और फार्मास्यूटिकल्स'' और ''इलेक्ट्रॉनिक्स'' में प्रवाह कम रहा है। ''हालांकि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग'', ''चिकित्सा और सर्जिकल उपकरण ।'' ''शिक्षा'', ''सेवाएं'' और ''रेलवे'' में प्रवाह अधिक था।

चित्र IX.8: वैश्विक अनिश्चितता ने एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह को नियंत्रित किया

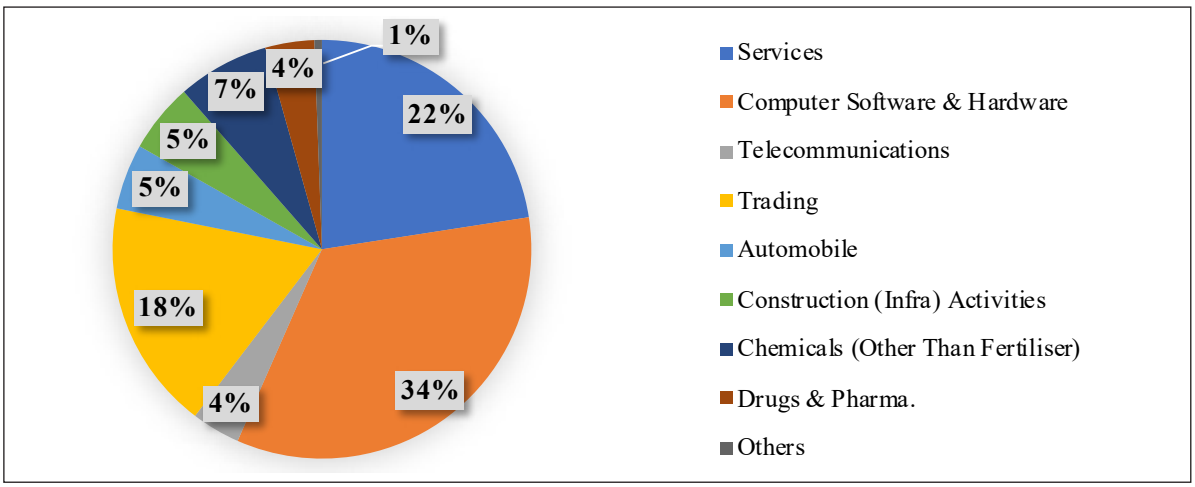

स्रोत: डीपीआईआईटी ऑकड़े

16. वित्त वर्ष 23 की पहली छमाही में एफडीआई में समग्र गिरावट के बावजूद, अंतर्वाह महामारी-पूर्व के स्तर से ऊपर रहा है, जो संरचनात्मक सुधारों और व्यापार करने में आसानी में सुधार के उपायों से प्रेरित है जिसके कारण भारत दुनिया एफडीआई के लिए सबसे आकर्षक गंतव्यों में से एक बन गया है। सरकार ने एक निवेशक-अनुकूल एफडीआई नीति लागू की है जिसके तहत अधिकांश क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग से 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति है। भारत ने, एफडीआई सीमा बढ़ाकर, नियामक बाधाओं को हटाकर, बुनियादी ढांचे के विकास और कारोबारी माहौल में सुधार करके अपने क्षेत्रों को वैश्विक निवेशकों के लिए खोलना जारी रखा हुआ है। इनसे आगे बढ़ते हुए, भारत में आने वाले पांच वर्षों में 475 बिलियन अमेरिकी डॉलर के एफडीआई प्रवाह को आकर्षित करने की क्षमता है जो पिछले वर्षों[2] में किए गए संरचनात्मक सुधार और नीतिगत समर्थन के कारण बेहतर विकास संभावनाओं से संभव हो सकेगा।

बॉक्स IX.2: निवेश को बढ़ावा देने के लिए एफडीआई नीति में सुधार

- भारत ने एफडीआई सीमा बढ़ाकर और बढ़ते निवेश को आकर्षित करने के लिए नियामक बाधाओं को हटाकर, बुनियादी ढांचे के विकास और कारोबारी माहौल में सुधार के अलावा, वैश्विक निवेशकों के लिए अपने क्षेत्रों को खोलना जारी रखा हुआ है। भारत को अधिक आकर्षक निवेश गंतव्य बनाने के लिए सरकार ने रक्षा, पेंशन, ई-कॉमर्स गतिविधियों आदि जैसे सभी क्षेत्रों में कई क्रांतिकारी और परिवर्तनकारी एफडीआई सुधारों को लागू किया है।
- प्रासंगिक अधिनियमों के प्रावधानों के अधीन संबद्ध प्रसंस्करण अवसंरचना सहित कोयला खनन गतिविधियों के लिए कोयले की बिक्री के लिए स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई थी। डिजिटल मीडिया के माध्यम से समाचार और करंट अफेयर्स को अपलोड/स्ट्रीम करने के लिए सरकारी प्रणाली के अंतर्गत 26 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई है। मध्यस्थों या बीमा मध्यस्थों में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई है और इनमें बीमा दलाल, फनर्बीमा दलाल, बीमा सलाहकार, कॉर्पोरेट एजेंट, तृतीय पक्ष प्रशासक, सर्वेक्षक और हानि निर्धारक तथा समय समय पर बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अधि सूचित अन्य संस्थाएं शामिल हैं।

- कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण/अधिग्रहण पर अंकुश लगाने के लिए, सरकार ने एफडीआई नीति में संशोधन किया, जिसके अनुसार किसी देश की कंपनी जो भारत के साथ एक भू-सीमा साझा करती है या जहां भारत में निवेश का लाभकारी स्वामी स्थित है या ऐसे किसी देश का नागरिक है तो वह केवल सरकारी प्रणाली के अंतर्गत ही निवेश कर सकता है। इसके अलावा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत में किसी कंपनी में किसी मौजूदा या भविष्य के एफडीआई के स्वामित्व के हस्तांतरण की स्थिति में, जिसके परिणामस्वरूप लाभकारी स्वामित्व कथित नीति संशोधन के प्रतिबंध/दायरे में आता है, लाभकारी स्वामित्व में इस तरह के बाद के परिवर्तन के लिए भी सरकार की मंजूरी आवश्यक होगी।
- विदेशी निवेश की स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए, मई 2017 में पूर्ववर्ती विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) को समाप्त कर दिया गया था और एक नई व्यवस्था लागू की गई है। नई व्यवस्था के तहत, एफडीआई अनुमोदन देने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिसमें एफडीआई के लिए आवेदनों के प्रसंस्करण से संबंधित कार्य, संबंधित मंत्रालयों/विभागों को सौंपे गए हैं, तथा प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए डीपीआईआईटी नोडल विभाग है।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सुविधा हेतु निवेशकों के लिए, भारत सरकार के ऑनलाइन एकल-बिंदु इंटरफेस के रूप में एक नया पोर्टल, ''विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल (एफआईएफ पोर्टल)'' लॉन्च किया गया है। पोर्टल उन आवेदनों की एकल खिड़की निकासी की सुविधा प्रदान करता है जो सरकारी अनुमोदन प्रणाली के माध्यम से होते हैं। एफआईएफ पोर्टल को नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) के साथ एकीकृत किया गया है।

औद्योगिक समूह एवं उनकी चुनौतियां

महामारी से भली-भांति उबरने पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई)

17. हालांकि समग्र जीवीए में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान वित्त वर्ष 18 के 29.3 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 30.5 प्रतिशत हो गया था परन्तु महामारी के आर्थिक प्रभाव के कारण वित्त वर्ष 21 में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी घटकर 26.8 प्रतिशत रह गई। वित्त वर्ष 21 में विनिर्माण क्षेत्र के जीवीए में एमएसएमई का योगदान भी मामूली रूप से घटकर 36.0 प्रतिशत रह गया

एमएसएमई का हिस्सा

चित्र IX.9a: निर्यात में एमएसएमई की हिस्सेदारी

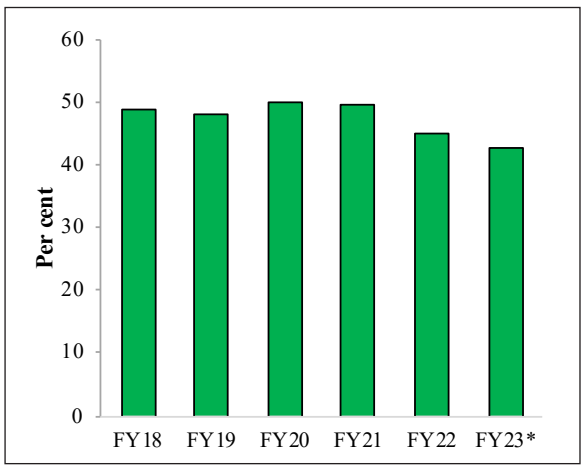

चित्र IX.9b: समग्र जीवीए और निर्माणकारी जीवीए में एमएसएमई की हिस्सेदारी

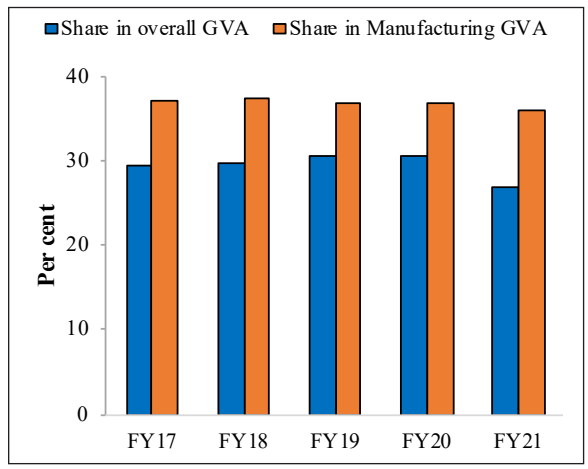

स्रोत: एमओएसपीआई, डीजीसीआई एण्ड एस
Note: *Data for FY23 is until Aug 2022

18. आत्मनिर्भर भारत पैकेज के माध्यम से, सरकार ने एमएसएमई पर महामारी के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। किए गए कुछ उपायों में, एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन; विपदग्रस्त एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपये के गौण ऋण का प्रावधान, आत्मनिर्भर भारत फंड के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपये इक्विटी इन्फ्यूजन; 200 करोड़ रुपये तक की खरीद के लिए वैश्विक निविदा आवश्यकता की छूट; एमएसएमई पंजीकरण के लिए उद्यम पोर्टल की शुरूआत, एक कागजरहित, मुफ्त पंजीकरण पोर्टल जो स्व-घोषणा पर आधारित है और इसके लिए केवल आधार की आवश्यकता होती है, उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण अगस्त 2022 में एक करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है, जो पिछले 14 वर्षों में पुरानी व्यवस्था के तहत किए गए कुल पंजीकरण को केवल 2.5 वर्षों में पार कर गया। 7 जनवरी 2022 तक, पोर्टल की कुल पंजीकरण संख्या 1.32 करोड़ है, जिसमें से 1.27 करोड़ को सूक्ष्म उद्यमों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पोर्टल पर पंजीकृत उद्यमों में 9.6 करोड़ लोग कार्यरत हैं, जिनमें से 2.3 करोड़ महिलाएं हैं। 1.5 लाख निर्यात इकाइयाँ हैं, जिन्होंने कुल 9.7 लाख करोड़ रुपये के निर्यात में योगदान दिया है।

19. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम के तहत एमएसएमई क्षेत्र की बकाया राशि की निगरानी के लिए स्थापित समाधान पोर्टल की सरकार की पहल, एमएसएमई को उनकी नकदी प्रवाह की कठिनाइयों को हल करने में मदद कर रही है। 7 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार, पोर्टल को कुल 1.3 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 16.8 प्रतिशत का निपटान किया जा चुका है, जबकि 25.0 प्रतिशत वर्तमान में विचाराधीन हैं और 25.1 प्रतिशत को खारिज कर दिया गया है। इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, सरकार ने सीपीएसई और 200 करोड़ रुपये या उससे अधिक के कारोबार वाली सभी कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे एक से अधिक वित्तदाताओं के माध्यम से एमएसएमई की व्यापार प्राप्तियों की छूट की सुविधा के लिए ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) प्लेटफॉर्म पर स्वंय को लाएं। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा जून 2020 में शुरू किए गए एमएसएमई के लिए सिंगल-विंडो शिकायत निवारण पोर्टल चौंपियन्स को, 24 मार्च 2022 तक 44,637 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 44,399 शिकायतों का जवाब दे दिया गया है। 11 क्षेत्रीय भाषाओं में पोर्टल के स्थानीयकरण और चौट बॉट की शुरूआत जैसी पहलों के माध्यम से पोर्टल में सुध ार जारी है।

20. सरकार ने वित्त वर्ष 23 में एमएसएमई के प्रदर्शन के उत्थापन और बढ़ाने (आरएएमपी) की पहल भी की है। विश्व बैंक समर्थित योजना का उद्देश्य केंद्र और राज्य में संस्थानों और शासन व्यवस्था को मजबूत करना, केंद्र-राज्य संबंधों और साझेदारी में सुधार करना और एमएसएमई की बाजार और ऋण तक पहुंच में सुधार करना, प्रौद्योगिकी उन्नयन और विलंबित भुगतान के मुद्दों को हल करना और एमएसएमई का कायाकल्प करना है। रैंप (आरएएमपी) कार्यक्रम पांच साल की अवधि में कार्यान्वित किया जाएगा। योजना के लिए कुल परिव्यय 6,062.4 करोड़ रुपये है, जिसमें से 3750 करोड़ रुपये विश्व बैंक से ऋण होगा और शेष 2312.4 करोड़ रुपये का वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा होगा।

21. सरकार द्वारा शुरू किए गए उपायों ने एमएसएमई क्षेत्र के लचीलेपन में मदद की है। राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यास कॉरपोरेशन (एनसीजीटीसी) के ऑकड़ों से पता चलता है कि 30 नवंबर 2022 तक, 1.2 करोड़ एमएसएमई इकाइयों ने आपदकालिक ऋण-व्यवस्था गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) का लाभ उठाया और संपार्श्विक-मुक्त संसाधनों को 3.6 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया। सीबिल (सीआईबीआईएल) की एक हालिया[2] रिपोर्ट से पता चला है कि ईसीएलजीएस का लाभ उठाने वाले 83 प्रतिशत उधारकर्ता सूक्ष्म-उद्यम थे और इनमें से आधे से अधिक उधारकर्ताओं का ऋण जोखिम 10 लाख रुपये से कम था। ईसीएलजीएस का लाभ उठाने वाले एमएसएमई उधारकर्ताओं की श्रेणी के लिए बैंकों में एनपीए की दर उस श्रेणी से कम थी जिसने योजना का

2 https://www.transunioncibil.com/resources/tucibil/doc/insights/reports/eclgs-insights-report.pdf

लाभ नहीं उठाया था। महामारी के झटके से एमएसएमई क्षेत्र की रिकवरी एमएसएमई इकाइयों द्वारा भुगतान किए गए जीएसटी के रुझान से स्पष्ट है। वित्त वर्ष 22 में क्षेत्र द्वारा किया गया भुगतान, वित्त वर्ष 20 में महामारी से पहले के स्तर को पार कर गया है।

चित्र IX.10: वित्त वर्ष 22 में एमएसएमई द्वारा जीएसटी भुगतान, महामारी-पूर्व स्तर को पार कर गया है।

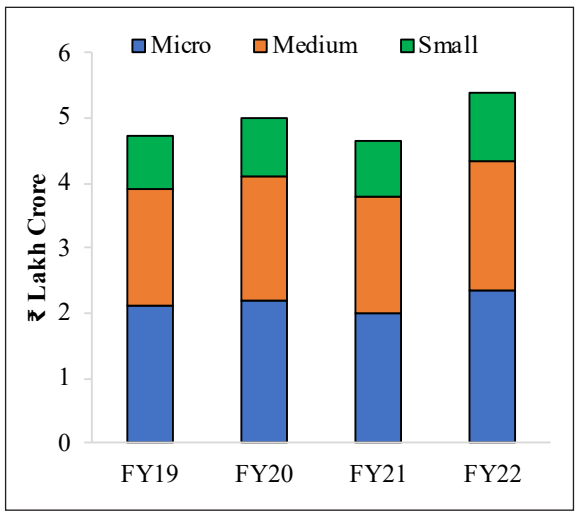

स्रोत: वित्त मंत्रालय
नोट: 1000 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर तक वाली कंपनियो सहित। सूक्ष्म -- <= 25करोड; लघु <= 25 से 100 करोड.; मध्यम 100 से 1000 करोड़।

चित्र IX.11: ईसीएलजीएस सहायता प्राप्त एमएसएमई, उनकी संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार

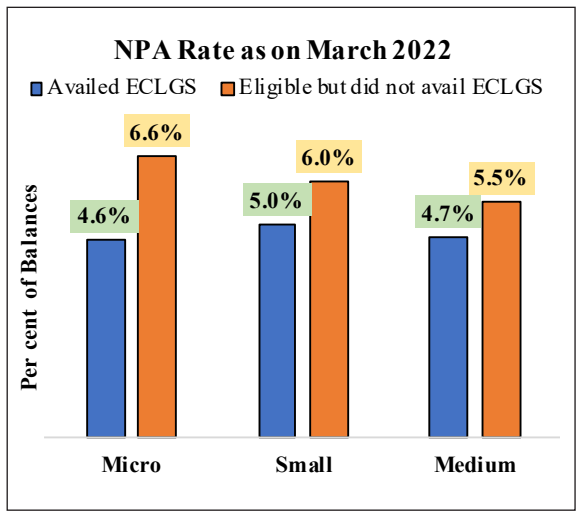

स्रोत: ईसीएलजीएस इनसाइट्स रिपोर्ट4, ट्रांसयूनियन सिबिल, अगस्त 2022

इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, विनिर्माण उत्पादन और निर्यात का होने वाला प्रमुख प्रेरक

22. इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का महत्व लगातार बढ़ रहा है क्योंकि इसके अनुप्रयोग व्यापक हो गए हैं, विशेष रूप से किसी देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में। संचार सेवाओं में होते निरंतर सुधार द्वारा समर्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, उत्पादकता, कुशल सेवा वितरण और सामाजिक परिखर्तन में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा। वित्त वर्ष 2020 तक घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का मूल्य 118 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। भारत का लक्ष्य 2025 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनना है और इस विजन को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 26[3] तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और 120 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के निर्यात तक पहुंचने का लक्ष्य है। पिछले पांच वर्षों में विनिर्माण और निर्यात में सुधार सुनिश्चित करता है कि भारत इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही रास्ते पर अग्रसर है। इलेक्ट्रॉनिक सामान अक्टूबर 2022 में सकारात्मक निर्यात वृद्धि प्रदर्शित करने वाले आवश्यक वस्तुओं के शीर्ष पांच समूहों में शामिल थे, इस खंड में निर्यात में (वर्ष-दर-वर्ष) 37.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

23. इस उद्योग में विकास के प्रमुख प्रेरक मोबाइल फोन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। मोबाइल फोन खंड में, भारत विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है, जिसके हैंडसेट का उत्पादन वित्त वर्ष 2015 के छह करोड़ यूनिट से बढ़कर वित्त वर्ष 22 में 31 करोड़ यूनिट हो गया है। अधिकाधिक घरेलू और वैश्विक उत्पादकों द्वारा भारत में अपने केंद्र स्थापित और विस्तारित करने से इन

3 https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1792189

संख्याओं में सुधार होने की उम्मीद है। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सेवाओं में दो प्रमुख वैश्विक और घरेलू उत्पादक, फॉक्सकॉन और डिक्सन, पहले ही पीएलआई योजना[4] को अपना चुके हैं। डिक्सन की तरह, पीएलआई योजना में भागीदारी से कई और घरेलू उत्पादकों को स्थानीयकरण के माध्यम से उत्पादन में बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था बनने में मदद मिलेगी। इसलिए, इससे निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता और बढ़ेगी और वैश्विक मूल्य श्रृंवला में भारत की भागीदारी बढ़ेगी। उद्योग 4.0 में, बेहतर डिजिटलीकरण और रोबोटिक्स अनुप्रयोगों के कारण औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में भी वृद्धि देखी जा रही है। इसके अतिरिक्त, स्मार्ट सिटीज और इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर जोर दिए जाने से, स्मार्ट और स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक्स की मांग सुव्यवस्थित होगी।

चित्र IX.12: इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में मजबूत वृद्धि (अप्रैल-अक्टूबर)

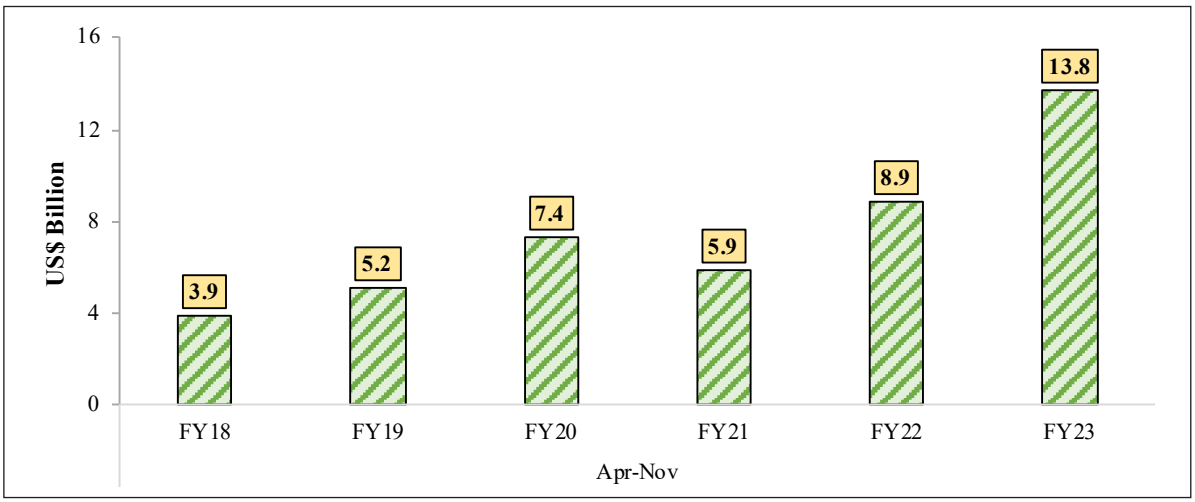

स्रोत: डीजीसीआईएण्डएस

24. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण आधार को पोषित करने और बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा की गई कुछ पहलों और प्रोत्साहनों में, बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना, आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और सेमीकंडक्टर्स (स्पेक) के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना शामिल है। इसके अलावा, भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए कार्यक्रम के तहत, कैबिनेट ने 76,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ देश में एक स्थायी सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले पारिस्थितिकी तंत्र के व्यापक विकास को मंजूरी दी है, जिसका विवरण बॉक्स 3 में दिया गया है। इन योजनाओं और पहलों से भारत की विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा मिलने, आयात पर निर्भरता कम होने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक प्रमुख भागीदार बनने की देश की महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने में भी योगदान मिलने की उम्मीद है।

बॉक्स IX.3: अमेरिका और भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन

कोविड-19 महामारी से वैश्विक आर्थिक सुधार ने कई वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति श्रृंखलाओं में कमजोरियों को उजागर किया है। एक उत्पाद जो सुर्खियों में था वह सेमीकंडक्टर (जिसे आमतौर पर 'चिप्स' के रूप से जाना जाता है) था और इसकी कमी का प्रभाव वैश्विक स्तर पर मोटर वाहन उद्योग में विशेष रूप से बढ़ा था। अब जबकि स्थिति पूर्ववत हो चुकी है और इसने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने के लिए देशों द्वारा नीतिगत प्रतिक्रिया को प्रेरित किया है।

4 https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1885189

सबसे उल्लेखनीय नीतियों में से एक, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सेमीकंडक्टर्स एण्ड साइंस एक्ट, 2022 (चिप्स एण्ड साइंस एक्ट, 2022) को तैयार करने के लिए प्रोत्साहन सहायता देना है। कानून का उद्देश्य अमेरिका की घरेलू सेमीकंडक्टर निर्माण क्षमता में निवेश को प्रेरित करना है। देश दुनिया के अर्धचालकों का लगभग 10 प्रतिशत उत्पादन करता है और चिप्स आयात करने के लिए पूर्वी एशिया पर बहुत अधिक निर्भर करता है। चिप्स एण्ड साइंस एक्ट में अगले दस वर्षों में 280 बिलियन अमेरिकी डॉलर वर्च करने की बात कही गई है, जिसमें से अधिकांश अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) में किया जाना है।

चित्र A: चिप्स एण्ड साइंस एक्ट, 2022 के अधीन प्रोत्साहन

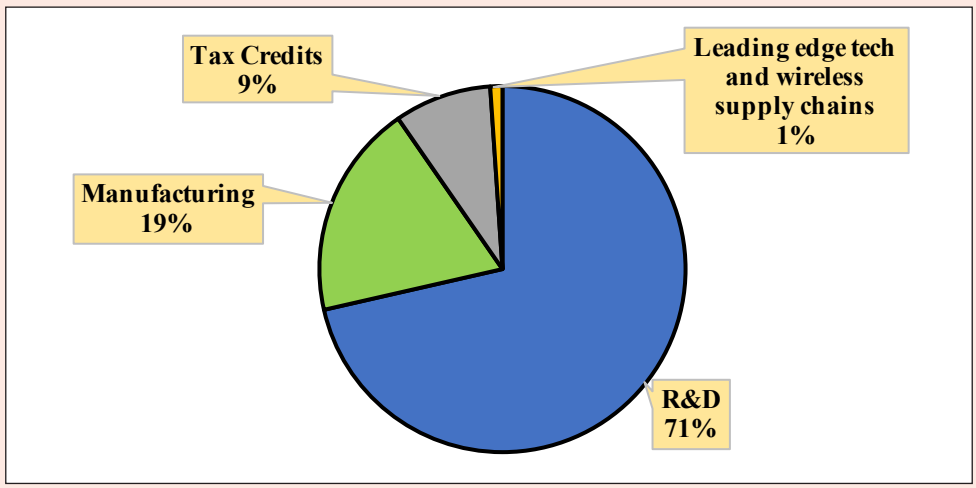

स्रोत: whitehouse.gov.in; मैककिनसे एंड कंपनी

आत्मनिर्भरता की खोज में और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में स्वंय को जोड़ने के उद्देश्य से, भारत ने सेमीकंडक्टर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने हेतु निवेश आकर्षित करने के लिए कई प्रोत्साहनों की घोषणा की है। इस दिशा में, सितंबर 2022 में भारत सरकार द्वारा 76,000 करोड़ रुपये (लगभग 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के परिव्यय के साथ एक व्यापक कार्यक्रम को मंजूरी दी गई थी। सरकार, निवेश कंपनियों द्वारा किए जाने वाले पूंजीगत व्यय के 50 प्रतिशत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

Table A: सेमीकंडक्टर योजना के अधीन अनेक प्रोत्साहन

के लिए योजना	वित्तीय समर्थन	रिसर्च एवं अनुसंधान समर्थन
भारत में सेमीकंडक्टर फैब की संस्थापना करने हेतु	कंपनी के कैपेक्स का 50 प्रतिशत	योजना परिव्यय का 2.5 प्रतिशत तक
डिस्प्ले फैब्स के संस्थापन हेतु	कंपनी के कैपेक्स का 50 प्रतिशत	योजना परिव्यय का 2.5 प्रतिशत तक
कंपाउंड सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर फैब और सेमीकंडक्टर एटीएमपी/ओएसएटी सुविधाओं की स्थापना	कंपनी के कैपेक्स का 50 प्रतिशत	योजना परिव्यय का 2.5 प्रतिशत तक

स्रोत: इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
नोट: एटीएमपी से तात्पर्य असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग है। ओएसएटी से तात्पर्या आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट है

यह जानते हुए कि भले ही भारत के पास दुनिया के सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरों का 20 प्रतिशत है, लेकिन बौद्धिक संपदा (आईपी) में एक मामूली हिस्सेदारी है, भारत सरकार ने डिजाइन लिंक्ड-इंसेंटिव (डीएलआई) योजना की भी घोषणा की है। योजना के उद्देश्यों में अर्धचालक डिजाइन की घरेलू कंपनियों का पोषण और उन्हे सुविधा प्रदान करना, देश भर में तैनात अर्धचालक उत्पादों और आईपी के महत्वपूर्ण स्वदेशीकरण को प्राप्त करना और डिजाइन के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना शामिल है। इस योजना में, डिजाइन पर प्रति आवेदक 15 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन, उपयुक्त व्यय के 50 प्रतिशत की वित्तीय सहायता और प्रति आवेदक 30 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन पांच वर्षों में प्राप्त शुद्ध बिक्री का 4 से 6 प्रतिशत नियोजनबद्ध प्रोत्साहन प्रदान करेगी।

यद्यपि ये शुरुआती चरण हैं, वैश्विक और घरेलू उत्पादकों ने भारत में अर्धकुशल उद्योग की संभावनाओं और प्रदान किए गए वित्तीय प्रोत्साहनों के आधार पर रुचि दिवाई है। इजराइल स्थित इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर कंसोर्टियम ने भारत का पहला चिप बनाने वाला संयंत्र स्थापित करने के लिए कर्नाटक में 22,900 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। वेदांता और टाटा जैसी घरेलू कंपनियों ने भी देश में सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने की योजना का संकेत दिया है।

कोयला उद्योग: अस्थिर समय के दौरान ऊर्जा आत्मनिर्भरता बनाए रखने की कुंजी

25. वित्त वर्ष की शुरुआत में, आर्थिक गतिविधियों में पुनरुत्थान और मार्च 2022 के मध्य से मई के मध्य तक हीट वेब के चलने के कारण, भारत के बड़े पैमाने पर थर्मल-आधारित बिजली उत्पादन संयंत्रों के लिए कोयले की उपलब्धता एक चुनौती बन गई, जिससे देश में ऊर्जा की मांग बढ़ गई। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय कोयले की बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए, ऊर्जा क्षेत्र ने वित्त वर्ष 20 में 69 मीट्रिक टन से वित्त वर्ष 21 में 45 मीट्रिक टन और आगे वित्त वर्ष 22 में 27 मीट्रिक टन तक कोयले के आयात में भारी कमी की। चूंकि, घरेलू कोयला उत्पादन, बिजली पैदा करने वाले संयंत्रों की बढ़ती मांग के साथ गति बनाए नहीं रख सका अत: इसकी उपलब्धता सीमित हो गई। परिणामस्वरूप, अप्रैल 2022 में, भले ही कोयले की मांग, अधिक मांग को पूरा करने के लिए बढ़ी और 31 अप्रैल 2022 तक बिजली संयंत्रों के पास कोयले के भंडारण की समयसीमा, एक साल पहले के 12 दिनों से कम होकर, 8 दिन हो गई।

26. भारत सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर कोयले की आपूर्ति की बाधाओं को दूर करने के लिए अप्रैल और मई 2022 के दौरान कई कदम उठाए। सबसे पहले, सभी उत्पादकों को अपनी आवश्यकताओं के 10 प्रतिशत (पहले के 4 प्रतिशत के मुकाबले) तक कोयले का आयात करने के लिए कहा गया था। बिजली संयंत्रों के कोयले का आयात करने में किल रहने पर घरेलू कोयले की हकदारी में कटौती सहित दंड की घोषणा की गई। दूसरा, विद्युत अधिनियम 2003 (अधिनियम) की धारा 11 को लागू किया गया था जिसके अंतर्गत सभी आयातित कोयला आधारित संयंत्रों को निर्देशित किया गया था कि वे पूरी संचालन क्षमता से प्रचालन करें और उनकी बढ़ी हुई प्रचालन लागत की भरपाई की जाएगी। तीसरा, टोलिंग को सक्षम किया गया, जिसने राज्यों को अपने आवंटित कोयले को राज्य के उत्पादकों से बहुत दूर ले जाने के बजाय खानों के पास निजी उत्पादक को स्थानांतरित करने की अनुमति दी। इस कदम से रेलवे रेक की उपलब्धता पर बोझ कम हो गया। चौथा, आरईसी/पीएफसी तथा वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी गई थी कि वे बिजली उत्पादन संयंत्रों को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की उपलब्धता की सुविधा प्रदान करें।

चित्र IX.13: पर्याप्त कोयला उत्पादन

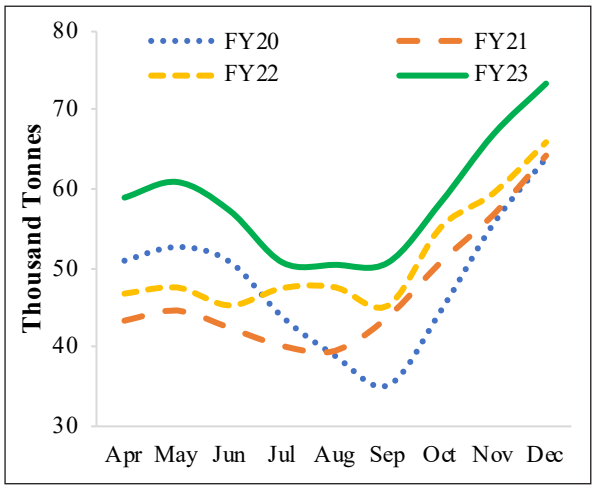

स्रोत: कोयला मंत्रालय

नोट: सीआईएल, एससीसीएल तथा कैप्टिव पावर प्लांट/अन्य द्वारा उत्पादन

चित्र IX.14: बढ़ता हुआ कोयला भंडार

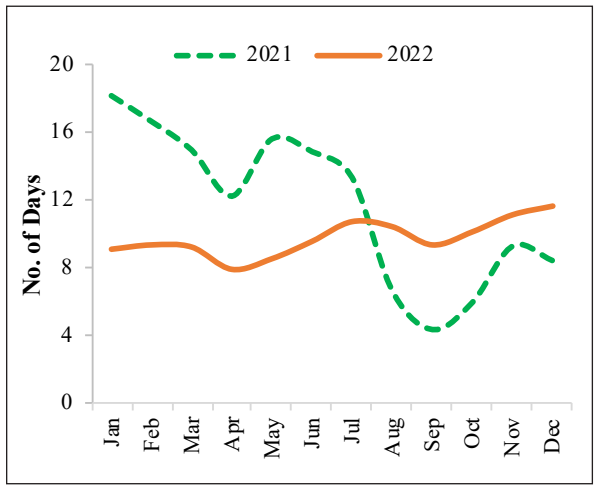

स्रोत: राष्ट्रीय ऊर्जा पोर्टल

27. समय रहते किए गए उपायों ने भारत को ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए बेहतर स्थिति में ला दिया है। वित्त वर्ष 23 के लिए कोयले का उत्पादन बढ़कर 911 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 17 प्रतिशत अधिक है। अप्रैल-अक्टूबर, 2022 में, कोयले का उत्पादन साल-दर-साल आधार पर 18 प्रतिशत बढ़ा और महामारी-पूर्व के वित्त वर्ष 20 की तुलना में 28 प्रतिशत अधिक था। इसके अलावा, बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार 30 जून 2022 को 10 दिनों और एक साल पहले 8 दिनों की तुलना में बढ़कर 30 दिसंबर 2022 तक 12 दिनों का हो गया है।

28. कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें कोयला उत्पादन में निजी भागीदारी, स्वचालित मार्ग के तहत एफडीआई, वाणिज्यिक उत्पादन के लिए कोयला ब्लॉकों की नीलामी, मौजूदा खानों का विस्तार और नई खदानें खोलना, खनन में बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रौद्योगिकी उपयोग, लोडिंग के लिए क्रिया-प्रणाली, निकासी के अवसंरचना का विकास आदि शामिल हैं।

29. कोयला उद्योग के वित्त वर्ष 26 तक 1 बिलियन टन और 2030 तक लगभग 1.5 बिलियन टन के उत्पादन स्तर तक पहुंचने के लिए सालाना 6-7 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। बढ़े हुए घरेलू कोयले के उत्पादन से घरेलू कोयले की मांग को पूरा करने, प्रतिस्थापन योग्य आयातों को बदलने और निर्यात के बढ़ने की उम्मीद है। प्रणाली क्षमता उपयोग को लगभग 80 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत से ऊपर करने का लगातार प्रयास किया गया है।

इस्पात उद्योग को चलाने के लिए अवसंरचना क्षेत्र और निर्माण गतिविधि को फिर से सक्रिय करना।

30. इस्पात क्षेत्र निर्माण, अवसंरचना, ऑटोमोबाइल, अभियांत्रिकी और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पिछले कुछ वर्षों में, इस्पात क्षेत्र में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। देश अब इस्पात उत्पादन में एक वैश्विक शक्ति है और दुनिया में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। चालू वित्त वर्ष में इस्पात क्षेत्र का अप्रैल-अक्टूबर 2022 के दौरान क्रमशः 68 मीट्रिक टन और 66 मीट्रिक टन तैयार इस्पात के संचयी उत्पादन और खपत के साथ अच्छा प्रदर्शन रहा है, जो पिछले चार वर्षों की इसी अवधि की तुलना में अधिक

है। तैयार इस्पात उत्पादन में वृद्धि को खपत में दो अंकों की वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 11 प्रतिशत) से समर्थन मिला है, जो सरकार के बढ़े हुए कैपेक्स द्वारा संचालित अवसंरचना के क्षेत्र में तेजी से बढ़ा है।

31. इसके अलावा, विशेष इस्पात के लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत 30 कंपनियों के 67 आवेदनों का चयन किया गया है। यह लगभग 26 मिलियन टन की क्षमता में वृद्धि और लगभग 70,000 लोगों की रोजगार सृजन क्षमता के साथ 42,500 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध निवेश को आकर्षित करेगा। इसके अलावा, घरेलू स्टील निर्माताओं की स्थिर क्रेडिट प्रोफाइल, घटती-बढ़ती बैलेंस शीट और मजबूत नकद संचय समर्थन उनके कैपेक्स का समर्थन करना जारी रखता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से यूरोप और चीन में मंदी और घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए लगाए गए निर्यात शुल्क के कारण चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में लौह और इस्पात निर्यात में धीमापन आया है। फिर भी, वित्त वर्ष 2020 के महामारी-पूर्व के स्तर की तुलना में लोहे और इस्पात का निर्यात 68 प्रतिशत अधिक है।

चित्र IX.15: इस्पात उत्पादन और खपत में वृद्धि

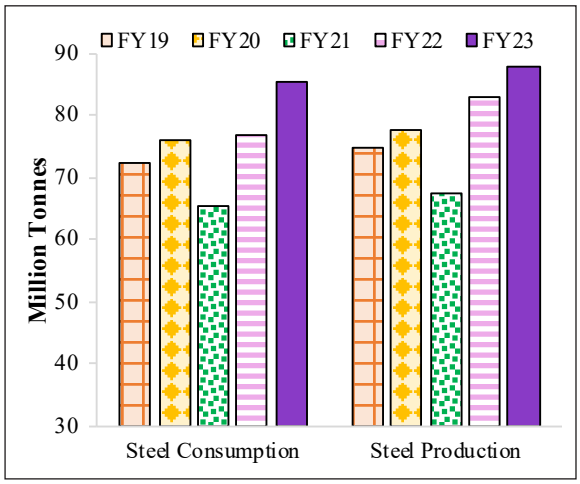

स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति, इस्पात मंत्रालय

चित्र IX.16: वित्त वर्ष 23 के दौरान लौह और इस्पात निर्यात में मामूली सुधार

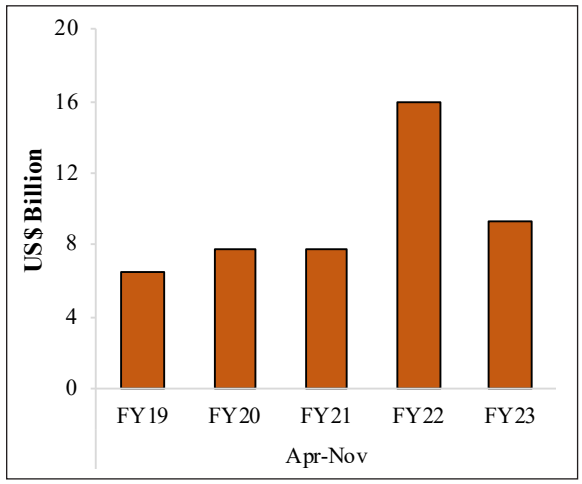

स्रोत: वाणिज्य विभाग

32. भविष्य में, अवसंरचना परियोजनाओं पर सरकार का जोर, निर्माण और रियल एस्टेट गतिविधि में तेजी और ऑटोमोबाइल क्षेत्र से मजबूत मांग इस्पात उत्पादों की मांग के लिए शुभ संकेत देती है। हालांकि, वैश्विक मंदी के साथ निर्यात मांग कमजोर रह सकती है, हालांकि घरेलू उपलब्धता में आसानी के बाद निर्यात शुल्क को हटाने से घरेलू स्टील उत्पादकों की निर्यात प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो सकती है और बदले में निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है।

कपड़ा उद्योग को मौजूदा चुनौतियों से निपटने में सहायता के लिए सरकारी समर्थन।

33. कपड़ा उद्योग देश के रोजगार सृजन के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है, अनुमान के आधार पर 4.5 करोड़ लोग सीधे इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण आबादी शामिल हैं। चालू वित्त वर्ष में, उद्योग, वित्त वर्ष 22 की तुलना में निर्यात में धीमी गति की चुनौती का सामना कर रहा है। हालाँकि, पहले छह महीनों में यह स्तर अभी भी महामारी-पूर्व के वित्त वर्ष 20 की इसी समयावधि की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है। इसी अवधि के दौरान रेडीमेड गारमेंट्स के निर्यात में साल दर साल आधार पर 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। कपड़ा क्षेत्र में एफडीआई का प्रवाह अभी भी पूर्व-महामारी के स्तर तक नहीं पहुंच पाया है।

चित्र IX.17: कपड़ा निर्यात में कमी आई, जबकि रेडीमेड गारमेंट निर्यात में तेजी आई है।

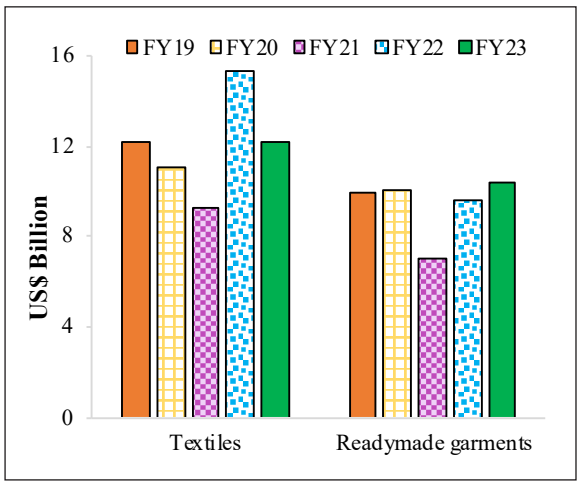

स्रोत: वाणिज्य विभाग

चित्र IX.18: कपड़ा उद्योग में एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह अभी तक बहाल नहीं हुआ है

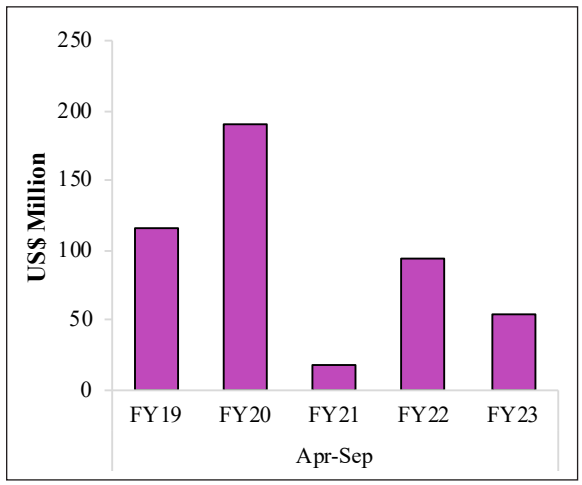

स्रोत: डीपीआईआईटी

34. कपड़ा उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए बड़े पैमाने पर एकीकृत और आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना सुविधाओं को विकसित करने के लिए, सरकार ने सात पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्रा) पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी है। पार्क न केवल अवसंरचना लागत को कम और भारतीय वस्त्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करेंगे बल्कि रोजगार सृजन को भी बढ़ावा देंगे, घरेलू निवेश और एफडीआई को आकर्षित करेंगे और भारत को वैश्विक कपड़ा बाजार में मजबूती से स्थापित करेंगे। पार्कों से कुल एक लाख प्रत्यक्ष और दो लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

35. इसके अलावा, उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने और मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) परिधान का उत्पादन बढ़ाने, एमएमएफ कपड़ों तथा तकनीकी वस्त्रों के उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले पांच वर्षों में 10,683 करोड़ रुपये के स्वीकृत परिव्यय के साथ, कपड़ा पीएलआई योजना शुरू की है। यह, कपड़ा क्षेत्र को आकार और पैमाना हासिल करने में सक्षम बनाएगा, जिससे निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। अब तक स्वीकृत 64 आवेदनों में, प्रस्तावित कुल निवेश प्रतिबद्धता 19,798 करोड़ रुपये है, जिसमें अनुमानित कारोबार और रोजगार सृजन क्रमशः 1.9 लाख करोड़ रुपये और 2.5 लाख करोड़ रुपये है। सरकार वर्तमान में वैश्विक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को और बढ़ाने के लिए पीएलआई 2.0 पर काम कर रही है जो कपड़ा मूल्य श्रृंखला में प्लेयर्स को प्रोत्साहन प्रदान करती है और इस उच्च विकास उद्योग खंड में भारत को पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करती है।

महामारी के बाद औषधि उद्योग में विकास की गति कायम है

36. भारतीय औषध उद्योग, वैश्विक औषध उद्योग में एक मुख्य भूमिका निभाता है। भारत के घरेलू औषध बाजार का 2021 में 41 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 2024 तक 65 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने और आगे 2030[5] तक 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। औषधीय उत्पादों के उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारत दुनिया भर में तीसरे और मूल्य के हिसाब से 14वें स्थान पर है। देश, वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है, जो मात्रा के हिसाब से वैश्विक आपूर्ति में 20 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है और 60 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ वैश्विक स्तर पर अग्रणी वैक्सीन निर्माता है।

5 https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1660739

चित्र IX.19: औषधि निर्यात में मजबूत वृद्धि

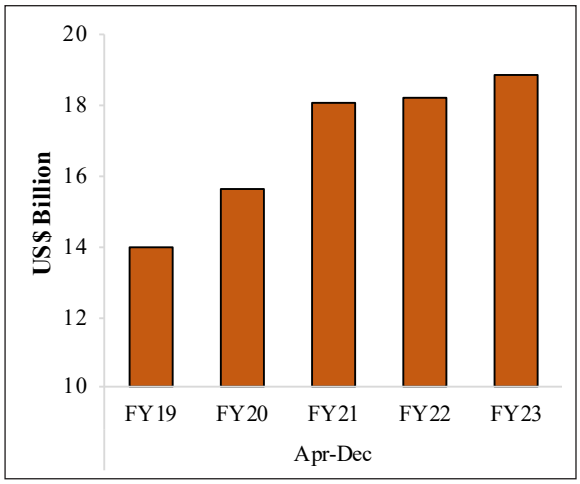

स्रोत: वाणिज्य विभाग

चित्र IX.20: औषध क्षेत्र में उच्च एफडीआई अंतर्वाह

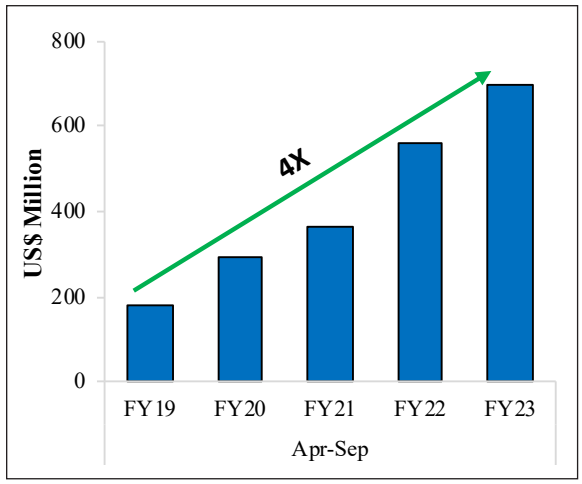

स्रोत: डीपीआईआईटी

37. भारतीय औषधि निर्यात ने वित्त वर्ष 2021 में 24 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि हासिल की, जो 150 से अधिक देशों को की गई महत्वपूर्ण दवाओं और अन्य आपूर्ति के लिए कोविड-19-उद्भूत मांग से प्रेरित है। वैश्विक व्यापार व्यवधानों और कोविड-19 से संबंधित उपचारों की मांग में गिरावट के बावजूद वित्त वर्ष 22 में औषधि निर्यात का प्रदर्शन मजबूत रहा है और इसमें निरंतर वृद्धि हुई है। इस विकास गति को आगे बढ़ाते हुए, अप्रैल-अक्टूबर 2022 के दौरान दवा और औषध निर्यात, वित्त वर्ष 20 की इसी पूर्व-महामारी अवधि की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक था। सितंबर 2022 में औषधि क्षेत्र में संचयी एफडीआई 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार कर गई है। इसके अलावा, सितंबर 2022 तक एफडीआई अंतर्वाह पांच वर्षों में चार गुना बढ़कर 699 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो निवेशक-अनुकूल नीतियों और उद्योग के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण द्वारा समर्थित है।

चित्र IX.21: औषधि क्षेत्र में विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए तीन पीएलआई योजनाएं

Critical KSMs/DIs/APIs	Medical Devices	Pharmaceuticals
• **Tenure**:FY21 to FY30 • **Outlay**: ₹6,940 crore • **Progress**: Until Dec 2022, 51 applicants approved with committed investment of ₹4,138.4 crore. • **Employment**: Estimated employment generation from 51 projects is 10,598 persons. • **Financial incentive**: NA	• **Tenure**: FY21 to FY28 • **Outlay**: ₹3,420 crore • **Progress**: Until Dec 2022, 21 applicants approved with committed investment of Rs 1,058.97 crore. • **Employment**: Estimated employment generation from 21 projects of around 6,411 persons. • **Financial incentive**: The financial incentive at the rate of 5 per cent on incremental sales of medical devices for 5 years.	• **Tenure**: FY21 to FY29 • **Outlay**: ₹15,000 crore • **Progress**: Until June 2022, 55 applicants approved with actual investment of Rs 18,669 crore. • **Employment**: Estimated employment generation from 55 projects : 20,000 direct and 80,000 indirect jobs. • **Financial Incentive**: on incremental sales under various categories at varying rate over the years ranging from 10 per cent to 3 per cent.

Source: Department of Pharmaceuticals

38. सरकार ने औषधि क्षेत्र की अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार के लिए कई उपाय किए हैं। संबंधित योजना अर्थात औषधि उद्योग का सुदृढीकरण (एसपीआई), 11 मार्च 2022 को कई उद्देश्यों के साथ वित्त वर्ष 22 से वित्त वर्ष 26 तक पाँच वर्षों के लिए 500 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य सर्वप्रथम औषधि समूहों को सामान्य सुविधाएं तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके मौजूदा बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है। दूसरा, यह एमएसएमई के पूंजी ऋणों पर ब्याज अनुदान या पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करके, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विनियामक मानकों को पूरा करने के लिए उनकी उत्पादन सुविधाओं का उन्नयन करता है। तीसरा, यह अध्ययन करके, डेटाबेस बनाकर और अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करने के लिए उद्योग जगत के अग्रणियों, शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं को एक साथ लाकर, औषधि और चिकित्सा उपकरण उद्योग के विषय में ज्ञान और जागरूकता को बढ़ावा देता है।

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया है

39. ऑटोमोबाइल क्षेत्र भारत के आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक है। 2022 में, भारत दोपहिया और तिपहिया वाहनों का सबसे बड़ा निर्माता और यात्री गाडियों का दुनिया का चौथा सबसे बड़ा निर्माता था। इस क्षेत्र का महत्व इस तथ्य से पता चलता है कि यह क्षेत्र, 2021 के अंत में 37 मिलियन का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करते हुए समग्र सकल घरेलू उत्पाद में 7.1 प्रतिशत और विनिर्माण सकल घरेलू उत्पाद में 49 प्रतिशत का योगदान देता है।[6]

चित्र IX.22: ऑटोमोबाइल की वृद्धिशील बिक्री

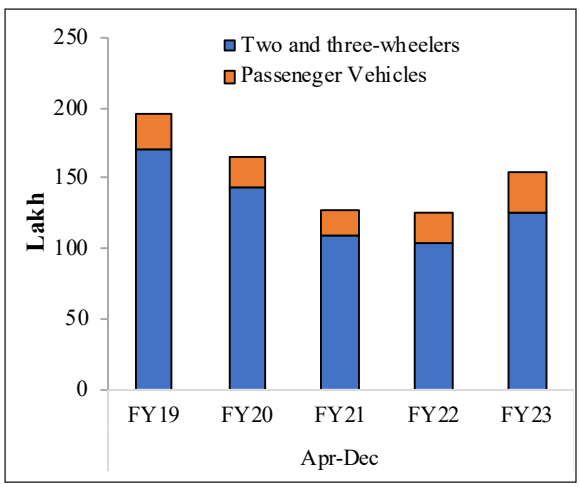

चित्र IX.23: कमजोर वैश्विक मांग के बीच ऑटोमोबाइल निर्यात में मंदी

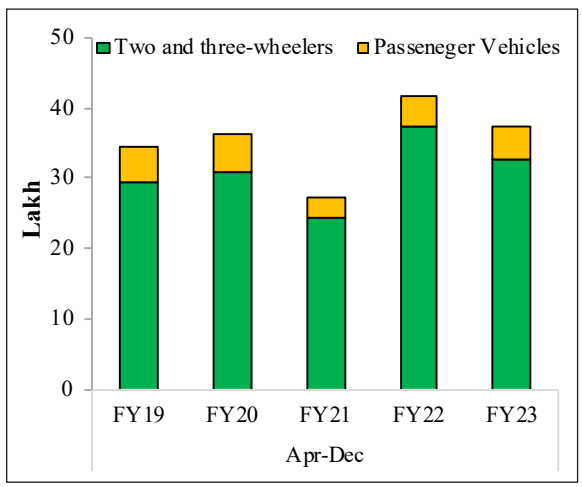

स्रोत: एसआईएएम

40. मोटर वाहन उद्योग के, हरित ऊर्जा की दिशा में परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। घरेलू इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बाजार के, 2022 और 2030 के बीच 49 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद है और 2030 तक दस मिलियन-यूनिट वार्षिक बिक्री तक पहुंचने की उम्मीद है। ईवी उद्योग 2030 तक 50 मिलियन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करेगा। इस विकास की सहायता और पोषण करने के लिए, सरकार ने कई कदम उठाए हैं।

6 https://www.investindia.gov.in/team-india-blogs/electric-vehicle-ev-sector-india-boost-both-economy-and-environment

चित्र IX.24: ऑटोमोबाइल की वृद्धिशील बिक्री

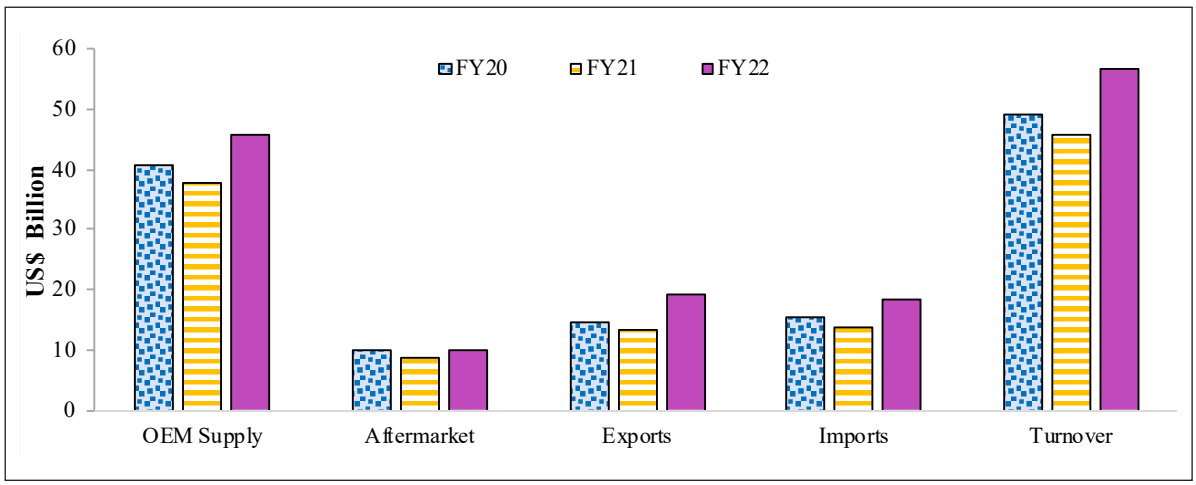

स्रोत: भारी उद्योग मंत्रालय
नोट: ओईएस से तात्पर्य मूल उपकरण विनिर्माण से है
आफ्टरमार्केट से तात्पर्य, मोटर वाहनों के लिए स्पेयर पार्ट्स, सहायक-उपस्कर और पुर्जों के बाजार से है।

चित्र IX.25: खपत बढ़ाने वाली प्रोत्साहन योजनाएँ

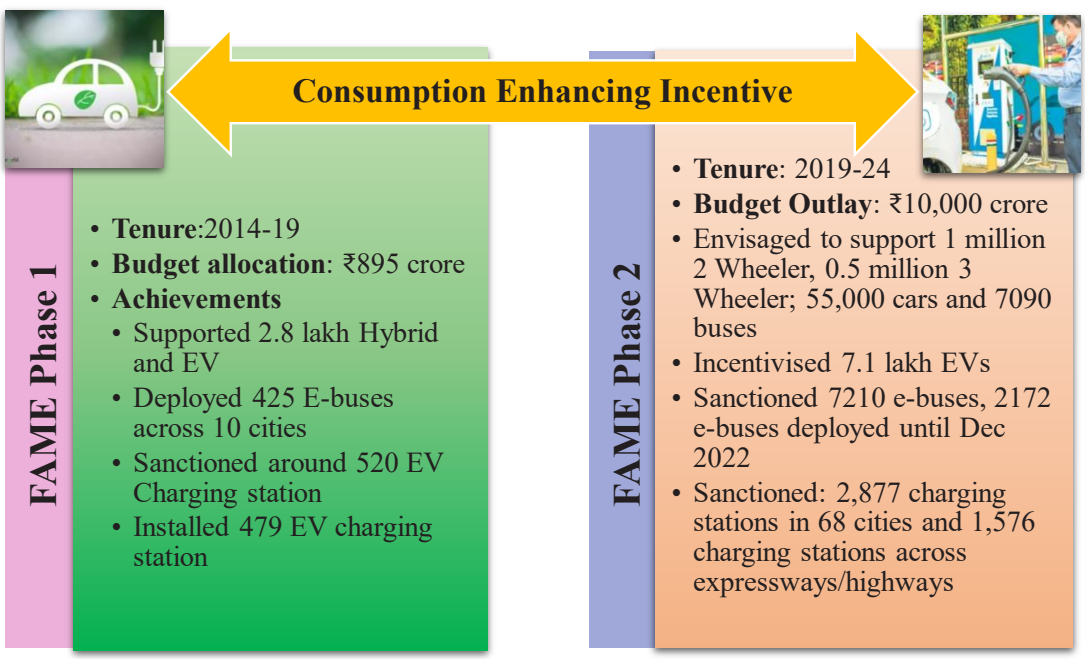

स्रोत: भारी उद्योग मंत्रालय
नोट: एफएएमई का तात्पर्य इलैक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण से है।

चित्र IX.26: उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाएं

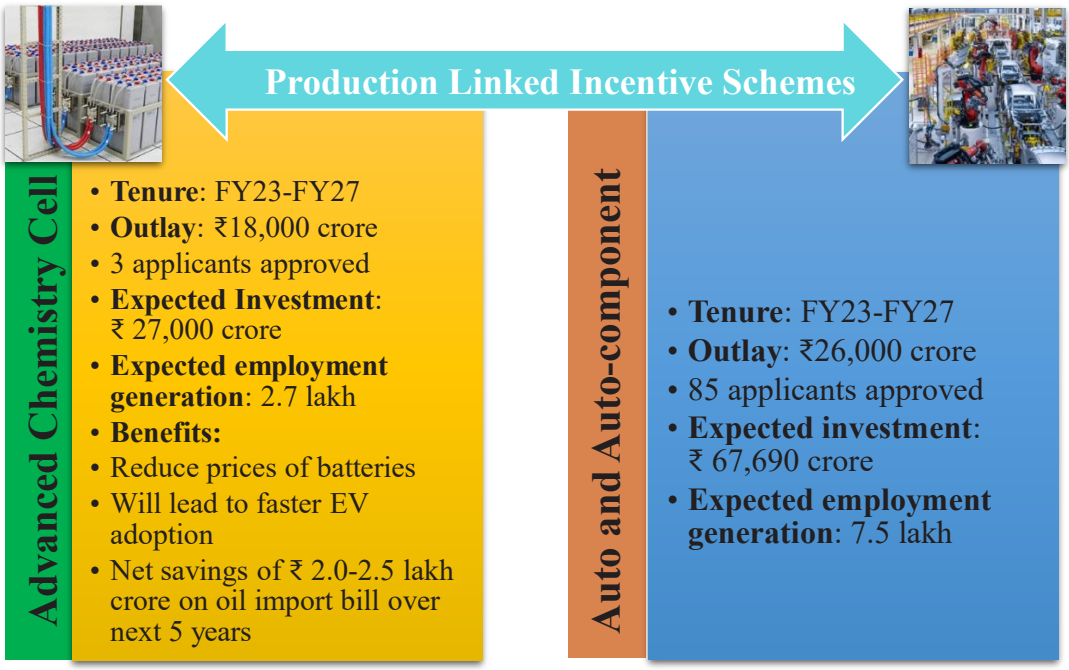

स्रोत: भारी उद्योग मंत्रालय

41. आशावादी दृष्टिकोण के बावजूद, मोटर वाहन उद्योग को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। निकट अवधि में, रुपये में गिरावट और उच्च ऋण लागत के एक उदास वैश्विक परिदृश्य में भागीदार बनने की उम्मीद है। संरचनात्मक मुद्दों के बीच, दीर्घकालिक तृतीय-पक्ष वाहन बीमा प्रीमियम में वृद्धि ने, कुल अग्रिम बीमा लागत विशेष रूप से दोपहिया वाहनों के लिए, में लगभग 10-11 प्रतिशत की वृद्धि की है। इसलिए, दोपहिया क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित है और पिछले दस वर्षों में इसमें सबसे कम बिक्री देखी गई है। इन चुनौतियों का समाधान करने से ऑटोमोबाइल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।

वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत की संभावनाएं

42. यूएस-चीन व्यापार युद्ध, कोविड-19 महामारी और यूक्रेन युद्ध के जटिल संकटों के बाद, आपूर्ति श्रृंखला के झटके का जोखिम, आज की तुलना में कभी भी इतना ज्यादा स्पष्ट नहीं रहा है। इस तेजी से विकसित होने वाले मामले में, जबकि वैश्विक कंपनियां बहाली के लिए अपनी विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला रणनीतियों को अपनाती हैं, भारत के पास इस दशक में वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने का एक अनूठा अवसर है। इस अनूठे अवसर को भुनाने के लिए भारत के पास बडे पैमाने पर युवा कार्यबल के साथ तीन प्राथमिक आस्तियां अर्थात महत्वपूर्ण घरेलू मांग की क्षमता, विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार का अभियान और एक बड़े अनुपात में विशिष्ट जनसांख्यिकीय बढ़त, मौजूद हैं। भारत में विनिर्माण क्षेत्र धीरे-धीरे अधिक स्वचालित और प्रक्रिया-संचालित विनिर्माण में स्थानांतरित हो रहा है, जिससे दक्षता में वृद्धि और उद्योग उत्पादन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का केंद्र बनाने के लिए 2014 में 'मेक-इन-इंडिया' पहल शुरू की गई थी। तब से, इसने निवेश तथा नवाचार को बढ़ावा दिया है और विश्व स्तरीय अवसंरचना का निर्माण किया है। अवसंरचना विकास में की गई प्रगति पर अध्याय ०० (अद्यतन किया जाना) में चर्चा की गई है।

घरेलू उत्पादन क्षमता में वृद्धि

43. वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत के समेकन को और बढ़ाने के लिए, मेक इन इंडिया 2.0 अब 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें 15 विनिर्माण क्षेत्र और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इनमें से 24 उप-क्षेत्रों को भारतीय उद्योगों की सामर्थ्य और प्रतिस्पर्धी बढ़त, आयात प्रतिस्थापन की आवश्यकता, निर्यात की संभावना और रोजगार में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए चुना गया है। समग्र और समन्वित तरीके से उप-क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने के प्रयास जारी हैं।

चित्र IX.27: मेक इन इंडिया 2.0 के अंतर्गत 24 उप-क्षेत्र

Source: DPIIT

44. मेक-इन-इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुसरण में और आत्मनिर्भरता हासिल करने की दृष्टि से, सरकार ने पीएलआई योजना शुरू की है। इस योजना से अगले पांच वर्षों में लगभग 3 लाख करोड़ रुपये कैपेक्स के होने की उम्मीद है। इसमें, भारत में 60 लाख से अधिक के लिए रोजगार पैदा करने और कुल पूंजीगत निर्माण में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ाने की क्षमता है, जो वर्तमान में वित्त वर्ष 12 और वित्त वर्ष 20 के बीच लगभग 17-20 प्रतिशत है। इसके अलावा, अगले पांच वर्षों में अधिक निर्यात के कारण निवल आयात में लगभग 35 से 40 ट्रिलियन रुपये तक की कमी आएगी। जिन क्षेत्रों के अंतर्गत पीएलआई योजना की घोषणा की गई है, वर्तमान में वे क्षेत्र कुल आयात का लगभग 40 प्रतिशत हैं। 14 क्षेत्रों में फैली यह योजना, वित्त वर्ष 23 से भारत के वार्षिक विनिर्माण कैपेक्स को 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ा सकती है। हालांकि, निष्पादन में देरी, वित्तपोषण की बढ़ती लागत, आवश्यक बुनियादी ढाँचे की उपलब्धता और अनुमोदन में देरी से संभावित चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

45. इन प्रमुख क्षेत्रों में पीएलआई योजना का कार्य, भारतीय निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना, मुख्य योग्यता और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना; दक्षता सुनिश्चित करना; विशाल अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण करना; निर्यात को बढ़ाना और भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला का एक अभिन्न अंग बनाना है। इस योजना से देश में एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ होगा। हर क्षेत्र में निर्मित एंकर इकाइयों को संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में नए आपूर्तिकर्ता स्थापित करने की आवश्यकता होगी। इनमें से अधिकतर सहायक इकाइयां, एमएसएमई क्षेत्र में तैयार की जाएंगी।

46. 31 दिसंबर 2022 तक, 14 योजनाओं के अंतर्गत 717 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। थोक में दवाएं, चिकित्सा उपकरणों, टेलीकॉम, व्हाइट गुड्स और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में पीएलआई लाभार्थियों में 100 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग शामिल हैं। कार्यान्वयन मंत्रालयों/विभागों की हाल की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 47,500 करोड़ रुपये (6 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का वास्तविक निवेश किया गया है; योग्य उत्पादों का 3.85 लाख करोड़ (47 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का उत्पादन/बिक्री और लगभग 3 लाख का रोजगार सृजन दर्ज किया गया है और वित्त वर्ष 22 के इसी समयावधि के अनुमानों की तुलना में वास्तविक निवेश में 106 प्रतिशत की उपलब्धि दर्ज की गई है। बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, औषधि, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, वाद्य प्रसंस्करण और व्हाइट गुड्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों ने निवेश, उत्पादन, बिक्री और रोजगार में काफी योगदान दिया है।

47. पीएलआई कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ नवीनतम परिवर्धनों में, जून 2022 में एक डिजाइन-आधारित पीएलआई का शुभारंभ शामिल है, जो दूरसंचार निर्माण में संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा देने और दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए पीएलआई योजना के हिस्से के रूप में 5जी के लिए एक मजबूत कारोबारी माहौल तैयार करने के लिए है। पात्र कंपनियों को इस योजना के अंतर्गत मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। सितंबर 2022 में, मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत में हाई-इफीसिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल के निर्माण के लिए कारोबारी माहौल तैयार करने और इस प्रकार नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में आयात निर्भरता को कम करने के लिए 19,500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 'हाई-इफीसिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल के राष्ट्रीय कार्यक्रम' पर पीएलआई योजना (ट्रांच II) को मंजूरी प्रदान की है।

बॉक्स IX.4: पोत निर्माण क्षेत्र: आत्मनिर्भरता हासिल करना और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना

पोत निर्माण उद्योग ऊर्जा सुरक्षा, राष्ट्रीय रक्षा और भारी इंजीनियरिंग उद्योग के विकास में अपनी भूमिका के कारण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। भारतीय नौसेना का लक्ष्य 2047 तक पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। यह क्षेत्र सहायक उद्योगों के साथ अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंधों के कारण मेक इन इंडिया पहल को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

सहायक उद्योग को बढ़ावा

पोत निर्माण में राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग और सेवा क्षेत्रों के योगदान को बढ़ाने की क्षमता है। पोत निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने से सहायक उद्योग भी विकसित होते हैं। अर्थव्यवस्था में अवसंरचना और सेवा क्षेत्रों पर इसकी व्यापक निर्भरता के अलावा, इस क्षेत्र का स्टील, एल्यूमीनियम, विद्युत मशीनरी और उपकरण आदि जैसे अन्य प्रमुख उद्योगों पर अत्यधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। निर्माणाधीन जहाज का लगभग 65 प्रतिशत मूल्यवर्धन शिपबोर्ड सामग्री, उपकरण और प्रणालियों के निर्माताओं से आता है।

महत्वपूर्ण निवेश और रोजगार सृजन गुणक प्रभाव

अंतर्राष्ट्रीय पोत निर्माण आंकड़ों के आधार पर, यदि कोई पोत निर्माण क्षेत्र के लिए 0.45 के जीडीपी अनुपात (एमसीजीआर) के परंपरागत सीमांत उपभोग पर विचार करता है, तो निवेश गुणक 1.82 तक काम करेगा। उदाहरण के लिए, नौसैनिक पोत निर्माण परियोजनाओं में लगभग ₹ 1.5 लाख करोड़ का एक निवेश 'गुणक प्रभाव' के कारण पोत निर्माण क्षेत्र में ₹2.73 लाख करोड़ का संचलन अर्जित करेगा।

विनिर्माण गतिविधियों में, पोत निर्माण 6.4[1] पर उच्चतम रोजगार गुणकों में से एक है। पोत निर्माण गतिविधि के स्थान को देखते हुए, यह दूरस्थ, तटीय और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा कर सकता है,

जिससे खेतों से पलायन करने वाले श्रम को शिपयार्ड और उनकी सहायक कंपनियों द्वारा स्थापित विनिर्माण सुविधाओं में आमेलित किया जा सकता है। भारतीय नौसेना द्वारा किए गए स्वदेशीकरण पहलों के परिणामस्वरूप एमएसएमई और अन्य उद्योगों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन हुआ है। उदाहरण के लिए, हाल ही में अधिकृत किए गए आईएनएस विक्रांत में लगभग 500 एमएसएमई, सहायक उद्योग के 12000 कर्मचारी और शिपयार्ड के 2000 कर्मचारी व्यस्त हैं।

इसके अलावा, सात पी17ए जहाजों के निर्माण के लिए नौसेना द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि युद्धपोतों की कुल परियोजना लागत का लगभग तीन-चौथाई भारतीय अर्थव्यवस्था में वापस निवेश किया जाता है। यह निवेश कच्चे माल के स्वदेशी संसाधनों, जहाजों पर स्थापित उपकरणों और प्रणालियों के विकास और अन्य संबंधित जनशक्ति सेवाओं के माध्यम से अर्थव्यवस्था में वापस लाया जाता है।

सहायक उद्योगों को लाभ पहुंचाने और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने के अलावा, एक स्वदेशी पोत परिवहन और पोत निर्माण उद्योग भी माल ढुलाई बिल और विदेशी मुद्रा व्यय को कम कर सकता है, जिससे चालू खाता घाटा कम हो सकता है।

नवाचार को बढ़ावा देना

48. नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार के प्रयासों में उद्भवन (इन्क्यूबेशन), हैन्डहोल्डिंग, वित्तपोषण, उद्योग-शिक्षा क्षेत्र की साझेदारी और सरंक्षण शामिल हैं। सरकार ने बौद्धिक संपदा कार्यालय का आधुनिकीकरण करके, कानूनी अनुपालनों को घटाकर और स्टार्ट-अप, महिला उद्यमियों, छोटे उद्योगों और अन्य लोगों के लिए आईपी फाइलिंग की सुविधा देकर अपनी बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था को भी मजबूत किया है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2016-2021 में पेटेंट की घरेलू फाइलिंग में 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर भारत के अवस्थांतर का संकेत है।

49. इन उपायों का लाभांश मिलना शुरू हो गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक (जीआईआई) नवाचार प्रदर्शन के आधार पर देशों को रैंक प्रदान करता है, जिसमें प्रत्येक अर्थव्यवस्था के राजनीतिक वातावरण, शिक्षा, अवसंरचना और ज्ञान निर्माण पर उपाय शामिल करते हुए लगभग 80 संकेतक शामिल हैं। जीआईआई 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, 2007 में जीआईआई की स्थापना के बाद से भारत ने वर्ष 2022 में पहली बार शीर्ष 40 नवाचारी देशों में प्रवेश किया है जो वर्ष 2015 में 81 से अपनी रैंक में सुधार करते हुए 2022 में 40 तक पहुँचा है। इसके अलावा, भारत निम्न मध्य-आय वर्ग वियतनाम (48वें) रैंक को पछाड़कर सबसे नवाचारी राष्ट्र बन गया है जो मध्य और दक्षिणी एशिया क्षेत्र का नेतृत्व कर रहा है।

बॉक्स IX.5: 'फ्लिपिंग एंड रिवर्स फ्लिपिंग: स्टार्ट-अप्स में हाल का घटनाक्रम'

भारत दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में शुमार है।डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स (सेल्फ-रिपोर्टेड) द्वारा प्रभावशाली 9 लाख+ प्रत्यक्ष नौकरियां सृजित की गई हैं।पिछले तीन वर्षों में सृजित नई नौकरियों की औसत संख्या की तुलना में 2022 में उल्लेखनीय 64 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हमारे लगभग 48 प्रतिशत स्टार्टअप टीयर II और III शहरों से हैं, जो हमारे सामान्य जन की जबरदस्त क्षमता का प्रमाण है।

सरकार की विभिन्न लक्षित पहलों ने स्टार्ट-अप्स को बहुत अधिक बढ़ावा दिया है। उदाहरण के लिए, स्टार्ट-अप इंडिया पहल के अंतर्गत, पात्र कंपनियों को कर लाभ, आसान अनुपालन और आईपीआर (बौद्धिक संपदा अधिकार) फास्ट-ट्रैकिंग के मेजबान के रूप में पहुँच के लिए डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्ट-अप के रूप में मान्यता दी जाती

है। विकास और दोहन नवाचार के लिए राष्ट्रीय पहल (एनआईडीएचआई) और अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) की अंब्रेला योजनाओं के एक भाग के रूप में, देश में स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र में उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा दिया जाता है। स्टार्ट-अप्स के लिए निधियों के कोष (एफएफएस) और स्टार्ट-अप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस), प्रारंभिक वित्तपोषण और क्रमिक क्रेडिट जरूरतों में सहायता करते हैं। अन्य के साथ-साथ,

प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के लिए अनुसंधान एवं विकास मंच जैसे कि एमईआईटीवाई स्टार्ट-अप हब (एमएसएच) और टेक्नॉलाजी इनक्यूबेशन एण्ड डेवलपमेंट ऑफ इंटरप्रेन्योर्स (टाइड 2.0) जैसी योजनाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वैश्विक मित्र-समूहों के साथ भारतीय स्टार्ट-अप को जोड़ना, स्टार्ट-अप इंडिया का एक अन्य आवश्यक स्तंभ है और इसे सरकार से सरकार की साझेदारी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भागीदारी और वैश्विक कार्यक्रमों की मेजबानी के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है। इसके अलावा, ई एंड आईटी (एसआईपी-ईआईटी) योजना में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट संरक्षण के लिए समर्थन, भारतीय एमएसएमई और स्टार्ट-अप[9] द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट फाइलिंग को प्रोत्साहित करता है।

चित्र A: स्टार्ट-अप्स के द्वारा सृजित नौकरियां

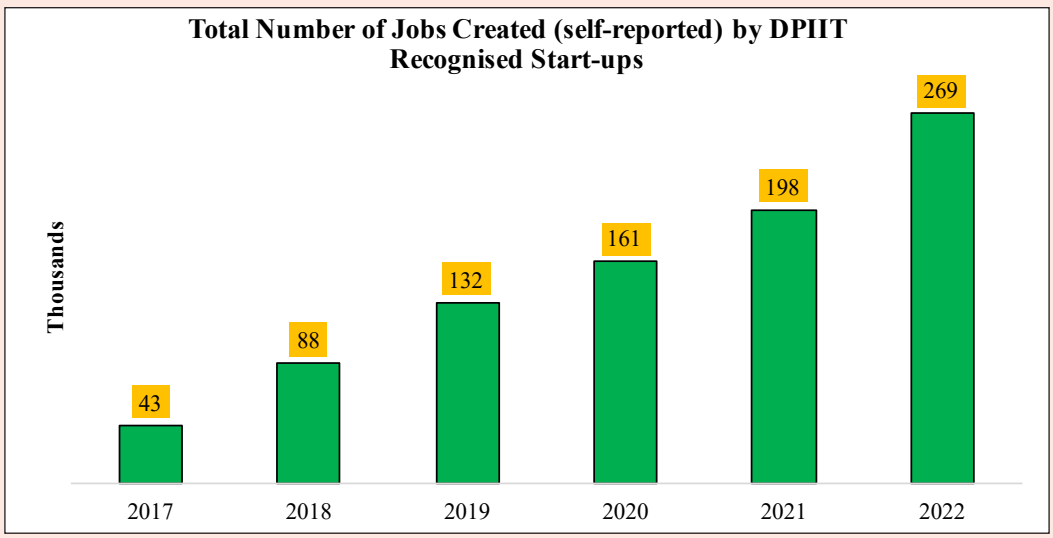

Note: Data as on 17th January 2023

जबकि सरकार के बाहरी समर्थन ने उद्यमशीलता को फलने-फूलने के लिए पहले की तुलना में अपेक्षाकृत आसान बना दिया है वहीं स्टार्ट-अप के सामने अंतर्निहित कई चुनौतियाँ हैं। भले ही यह भ्रामक वित्तपोषण, राजस्व सृजन संघर्ष, सहायक अवसंरचना तक आसान पहुँच की कमी हो या नियामक वातावरण और कर संरचनाओं से बचकर भागना हो। यह भी देवा गया है कि कई भारतीय कंपनियों के मुख्यालय विदेशों में स्थापित हो रहे हैं, विशेष रूप से अनुकूल कानूनी वातावरण और कराधान नीतियों वाले गंतव्यों में। इसके लिए तकनीकी शब्दजाल को 'फ्लिपिंग' के रूप में पहचाना जा सकता है, जो एक भारतीय कंपनी के संपूर्ण स्वामित्व को एक विदेशी संस्था को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है, जिसमें सभी बौद्धिक संपदा (आईपी) और अब तक भारतीय कंपनी के स्वामित्व वाले सभी डेटा का हस्तांतरण होता है। यह प्रभावी रूप से एक भारतीय कंपनी को एक विदेशी कंपनी की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी में पखिर्तित कर देता है, जिसके संस्थापक और निवेशक सभी शेयरों की अदला-बदली करके विदेशी कंपनी के माध्यम से समान स्वामित्व बनाए रखते हैं।

आमतौर पर, ''फ्लिपिंग'' स्टार्ट-अप के शुरुआती चरण में होता है, जो वाणिज्यिक, कराधान और संस्थापकों और निवेशकों की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं से प्रेरित होता है। कुछ कंपनियां ''फ्लिप" करने का निर्णय इसलिए लेती

7 Source: PIB https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1884256, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx-?PRID=1884069#:~:text=PLI%20Scheme%20extends%20an%20incentive,2020

हैं क्योंकि उनके उत्पाद का मुख्य बाजार बाहर स्थित होता है। कभी-कभी, इनक्यूबेटरों तक पहुंच जैसी निवेशक प्राथमिकताएं कंपनियों को ''फ्लिप'' करने के लिए प्रेरित करती हैं क्योंकि वे एक विशेष स्थान पर रहने पर जोर देते हैं। कुछ कंपनियां उन देशों में रहना पसंद करती हैं जहां वे बाद में बेहतर मूल्यांकन और टिकट साइज के लिए पूंजीगत बाजार तक पहुंच बनाना चाहती है। बौद्धिक संपदा (आईपी) की बेहतर सुरक्षा और प्रवर्तन तथा बौद्धिक संपदा से लाइसेंसिंग राजस्व का कर उपचार, संस्थापकों की आवासीय स्थिति और कुशल कॉर्पोरेट संरचनाएं, अतीत में ''फ्लिपिंग'' के कारण रहे हैं।

सिंगाफर जैसे लोकप्रिय स्वामित्व वाली (होल्डिंग) कंपनी के क्षेत्राधिकार में, सिंगापुर की कंपनी/सहायक कंपनी से प्राप्त लाभांश पर स्वामित्व (होल्डिंग) स्तर पर कर नहीं लगाया जाता है। निवासियों या अनिवासी शेयरधारकों को लाभांश वितरित करते समय इस पर कोई रोक नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण घटक है चूंकि लाभांश सर्वाधिक

लोकप्रिय प्रत्यावर्तन उपकरणों में से एक है। मौजूदा कानून के तहत यूएई में कोई विदहोल्डिंग कर (टैक्स) नहीं है। इन अधिकार-क्षेत्रों ने कंपनियों को बौद्धिक क्षमता स्टोर करने और धारक कंपनियों को क्षेत्रीय मुख्यालय के रूप में बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अपनी नीतियों और कर और प्रोत्साहन संरचनाओं को तैयार किया है। यूरोपीय अधिकार-क्षेत्र जैसे कि नीदरलैण्ड लाभांश तथा पूंजीगत लाभ (कुछ शेयरहोल्डिंग थ्रेशोल्ड, अर्थात 5 प्रतिशत और अन्य परीक्षणों के आधार पर) पर भागीदारी की छूट प्रदान करते हैं। ये छूट वर्तमान में भारत में उपलब्ध नही हैं और भारत में मौजूदा संरचनाओं का कोई भी देशान्तरण पूंजीगत लाभ कर को सक्रिय करता है। हालांकि, हाल ही में, एक व्यावसायिक निजी इक्विटी/उद्यम पूंजीगत पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से पूंजी तक अपेक्षाकृत आसान पहुंच के साथ, राउंड-ट्रिपिंग के संबंध में नियमों में बदलाव और भारत के पूंजीगत बाजारों की बढ़ती परिपक्वता ने न केवल फ्लिपिंग को धीमा कर दिया है, बल्कि कंपनियां ''रिवर्स फ्लिपिंग" के विकल्पों को भी अपना रहीं हैं।

चित्र B: कंपनी की संरचना पर फ्लिपिंग का प्रभाव

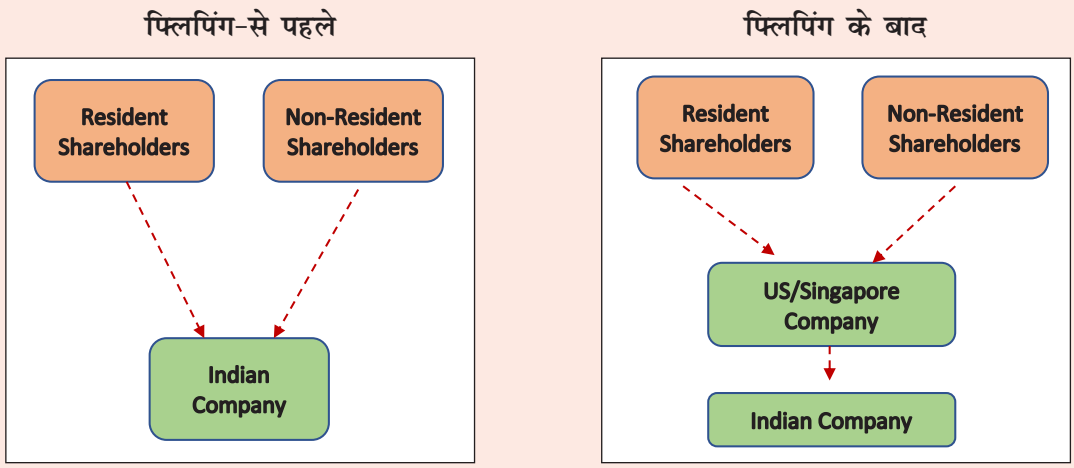

'रिवर्स फ्लिपिंग' में तेजी लाने के लिए कुछ उपाय संभव हैं, जिनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं:

i. स्टार्ट-अप्स के लिए ''अंतर्मंत्रालयी बोर्ड (आईएमबी) प्रमाणन" प्रदान करने की प्रक्रिया का सरलीकरण

ii. कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ईएसओपी) के कराधान का और सरलीकरण

iii. कर की कई परतों और कर मुकदमेबाजी के कारण अनिश्चितता को सरल बनाना

iv. पूंजी अंतर्वाह के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना: अमेरिका और सिंगापुर जैसे कई देशों में आसान कॉर्पोरेट कानून हैं, जिसमें पूंजी के प्रवाह और बहिर्वाह पर कम प्रतिबंध और संकर (हाईब्रिड) प्रतिभूतियों का उपचार है।

v. सर्वोत्तम प्रणालियों और अत्याधुनिक स्टार्ट-अप परामर्श प्लेटफार्मों को विकसित करने के लिए स्थापित निजी संस्थाओं के साथ बेहतर सहयोग और साझेदारी की सुविधा प्रदान करना

vi. सामाजिक नवाचार और प्रभाव निवेश जैसे उभरते क्षेत्रों में स्टार्ट-अप के लिए उद्भवन (इन्क्यूबेशन) और वित्तपोषण परिदृश्य की खोज करना।

गतिशील, अनिश्चित भू-राजनीतिक विश्व में अल्प-कालिक लाभ के लिए स्टार्ट-अप उद्यम के रूप में ऊपर उल्लिवित फ्लिपिंग घटना चर्चा का विषय हो सकती है। हालांकि, फ्लिप को सरकार से संबंधित नियामक निकायों और अन्य हितधारकों द्वारा सामूहिक कार्रवाई के साथ फनर्बहाल किया जा सकता है। समाधान-उन्मुव रणनीतियों के साथ, स्टार्ट-अप भारत की उद्यमशीलता की गतिशीलता के संदेशवाहक बने रहेंगे।

ढांचागत सुधारों से व्यापारिक सुगमता में वृद्धि हुई है

50. मेक इन इंडिया पहल यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि देश में व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र, भारत में व्यापार करने वाले निवेशकों के लिए अनुकूल है और देश के संवर्धन और विकास में योगदान दे रही है। यह अनेक सुधारों के माध्यम से किया गया है जिससे निवेश अंतर्वाह और आर्थिक विकास में वृद्धि हुई है। सुधार के उपायों में, कानूनों में संशोधन और अनुपालन के बोझ को कम करने, लागत में कमी लाने और भारत में व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने के लिए दिशानिर्देशों और विनियमों का उदारीकरण शामिल है। सरलीकरण, युक्तिकरण, गैर-अपराधीकरण और डिजिटलीकरण के माध्यम से नियमों और विनियमों के बोझिल अनुपालन को कम किया गया है, जिससे भारत में व्यापार करना आसान हो गया है। इसके अतिरिक्त, श्रम सुधार से नियुक्त करने और छंटनी करने में लचीलापन आया हैं। स्थानीय विनिर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किए गए हैं। विनिर्माण और निवेश को बढ़ावा देने के उपायों में कॉर्पोरेट करों को कम करना, सार्वजनिक खरीद आदेश और चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम शामिल हैं।

51. उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) की व्यवसाय सुधार कार्य योजना (पीआरएपी) 2020 (पांचवां संस्करण), राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सुधारों के कार्यान्वयन के आधार पर, 30 जून 2022 को जारी किया गया था। यह दर्शाता है कि बीआरएपी 2020 मूल्यांकन के भाग के रूप में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 7,496 सुधार लागू किए गए थे, जिससे देश भर में व्यापारिक सुगमता में काफी वृद्धि हुई है। व्यवसायों और नागरिकों पर अनुपालन बोझ (आरसीबी) को कम करना, शासन उत्कृष्टता के ऊंचे स्तर तक पहुँचने और जीवन सरलता में सुधार करने का एक सतत अभ्यास है। मंत्रालयों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 39,000 से भी अधिक अनुपालनों को कम कर दिया है। इसके विपरीत, डीपीआईआईटी के विनियामक अनुपालन पोर्टल पर अपलोड किए गए विवरण के आधार पर मंत्रालयों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा, मामूली तकनीकी और प्रक्रियात्मक चूक से संबंधित 3,400 से अधिक प्रावधानों पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा, राष्ट्रीय एकल विड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) को सितंबर 2021 में अनुमोदन और मंजूरी के लिए निवेशकों को एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करके व्यापारिक सुगमता में सुधार करने के लिए शुरू किया गया था। पोर्टल तेजी से निवेशक समुदाय के बीच लोकप्रिय हो रहा है और 1 दिसंबर 2022 तक इसके लगभग 3.7 लाख से अधिक अनेक विजिटर हो चुके हैं। एनएसडब्ल्यूएस के माध्यम से 44,000 से अधिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं और 28,000 से अधिक अनुमोदन वर्तमान में प्रक्रियाधीन हैं। पोर्टल, यूजर/उद्योग फीडबैक के आधार पर उत्तरोत्तर अधिक अनुमोदन और लाइसेंस प्रदान करेगा। इस पोर्टल ने निवेशकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की कई मौजूदा निकासी प्रणालियों को एकीकृत किया है।

भारत और उद्योग 4.0

52. चौथी औद्योगिक क्रांति अथवा उद्योग 4.0, जैसा कि आमतौर पर उल्लेख किया जाता है का आगमन शुरू हो गया है। परिवर्तन क्लाउड कंप्यूटिंग, आईओटी, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसी नई

तकनीकों को विनिर्माण प्रक्रियाओं में एकीकृत करता है, जिससे मूल्य श्रृंखला में प्रभावकारिता आती है। जबकि भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में इन प्रौद्योगिकियों को अपनाने का काम चल रहा है, बड़े पैमाने पर इसको अपनाया जाना अभी बाकी है। तथापि, एक सक्षम वातावरण तेजी से विकसित हो रहा है। हाल के वर्षों में, भारत ने इंटरनेट की पहुंच में महत्वपूर्ण प्रगति की है जो उद्योग 4.0 की प्रमुख आवश्यकताओं में से एक है। सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी और उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने से भारत को इस क्रांति-अति-कुशल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का एक और स्तंभ खड़ा करने में मदद मिलेगी।

53. सरकार आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उद्योग 4.0 के महत्व और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की अपनी महत्वाकांक्षाओं से अवगत है। सरकार द्वारा की गई कुछ पहलों में भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के तहत समर्थ (स्मार्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब) उद्योग भारत 4.0 शामिल है, जिसका उद्देश्य जागरूकता कार्यक्रमों और प्रदर्शनों के माध्यम से भारतीय विनिर्माण इकाइयों के लिए तकनीकी समाधान को बढ़ावा देना है। एक अन्य पहल 2018 में भारत में चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए केंद्र की स्थापना करना है, जो उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए नीतिगत ढांचे को विकसित करेगा।

निष्कर्ष और दृष्टिकोण

54. वैश्विक विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, वित्त वर्ष 23 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई जो लगातार मांग की स्थिति से समर्थित थी। जनवरी 2022 से स्पष्ट वृद्धि के साथ, बैंक ऋण में वृद्धि ने औद्योगिक विकास के साथ गति बनाए रखी है। आपातकालीन क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की शुरुआत से सहायता प्राप्त सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के ऋण में भी आंशिक रूप से उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के बीच, वित्त वर्ष 23 की पहली छमाही में विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में कमी आई है। हालांकि, अंतर्वाह पूर्व-महामारी के स्तर से काफी ऊपर रहा, जो संरचनात्मक सुधारों और व्यापारिक सुगमता में सुधार के उपायों से प्रेरित था, जिससे भारत दुनिया में सबसे आकर्षक एफडीआई गंतव्यों में से एक बन गया।

55. सकारात्मक पक्ष पर, जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में गिरावट के कारण इनफट लागत दबाव कम होना, कंपनी के मार्जिन के लिए अच्छा संकेत है। विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता उपयोग बढ़ रहा है। यह अतिरिक्त क्षमता सृजित करने में नई निवेश गतिविधि के लिए शुभ संकेत है। उद्योग जगत में ऋण वृद्धि भी उल्लेवनीय रूप से बढ़ी है, जो यह सुझाव दे रही है कि कंपनियों द्वारा कैपेक्स निवेश की संभावनाएं उज्जवल हैं। पीएलआई योजनाएं विनिर्माण क्षमता को अनलॉक करने, निर्यात को बढ़ावा देने, आयात पर निर्भरता कम करने और कुशल और अकुशल श्रम दोनों के लिए रोजगार सृजन के लिए तैयार हैं। हालांकि, नकारात्मक पक्ष देखें तो, निर्यात धीमा हो रहा है और संभावित वैश्विक आर्थिक मंदी के साथ-साथ इसके धीमा होने की संभावना है। वैश्विक स्तर पर नए व्यवधानों को देखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय आवश्यक वस्तुओं की अस्थिर कीमतें और कच्चे माल की आपूर्ति में व्यवधान, औद्योगिक विकास पर दबाव डाल सकते हैं। चीन में कोविड-19 के फिर से उभरने से आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान पैदा हो सकता है, जैसा कि महामारी के दौरान हुआ था। दूसरी ओर, यदि चीन कोविड-19 से उभरकर सामान्य स्थिति में लौटता है, तो आवश्यक वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो सकती है - इस प्रकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में हाल की गिरावट को रोका जा सकता है। बेशक, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में पुनर्बहाली की क्षमता और अवधि, कई कारकों जैसे कि चीन की आर्थिक सुधार की गति और उत्तरी अमरीका और यूरोप में विकास दृष्टिकोण का एक कार्य होगा। इस तरह के अनुत्तरित प्रश्नों के बावजूद, भारत में औद्योगिक उत्पादन लचीली घरेलू मांग के आधार पर लगातार बढ़ता रहना चाहिए।